mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-1 अंक-105 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

मनेन्द्रगढ़
16 अक्टूबर 2025 गुरुवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

या रोहित और विराट...
@ पेज 7

हाईकोर्ट का फैसला-चढ़ावे की राशि से नहीं बनेगी सड़कें, धन देवता का, सरकार का नहीं

वीआईपी को गिफ्ट और अधिकारी को गाड़ी खरीदने पर रोक

शिमला, एजेंसी। हिमाचल सरकार अब मंदिरों में चढ़ावे का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट ने दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए मंगलवार को एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने कहा- दान की राशि सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों के निर्माण पर खर्च नहीं होगी। जो काम सरकारों द्वारा कराए जाते हैं और मंदिर से जुड़े नहीं है, उन पर मंदिरों का बजट खर्च नहीं होगा। कोर्ट ने आगे कहा- दान की रकम से मंदिर कमिश्नर व मंदिर अधिकारी को वाहन भी नहीं खरीदे जा सकेंगे। मंदिरों में आने वाले VIP के लिए उपहार खरीदने (स्मृति चिन्ह, तस्वीरें, मंदिर की तस्वीर) पर भी कोर्ट ने रोक लगाई है। इसी तरह किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना, निजी व्यवसायों या उद्योगों में निवेश, दुकानें, मॉल या होटल चलाने के लिए इस राशि का उपयोग वर्जित किया है।

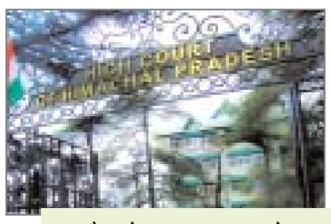

इस फैसले का क्या असर होगा : हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार अब मनमर्जी से मंदिरों का पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। चढ़ावे की राशि का उपयोग हाईकोर्ट के आदेशानुसार चुनिंदा कार्य पर ही किया जा सकेगा। इससे मंदिरों के पैसे की बंटरबांट रुकेगी। मंदिर अधिकारियों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा।

सरकारी नियंत्रण में 36 मंदिर : प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में 36 मंदिर हैं। इनमें देशभर से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए चढ़ावे के तौर पर देते हैं। भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के अनुसार, इन मंदिरों में 4 अरब से भी ज्यादा की राशि चढ़ावे के रूप में है।

जनहित याचिका क्यों डाली गई : प्रदेश की मौजूदा और पूर्व दोनों सरकार ने मंदिरों का पैसा लिया है। कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2025 में सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों को अंशदान देने को कहा था।

सोनम वांगचुक अरेस्ट केस- सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को सुनवाई

पत्नी गीतांजलि ने कहा, वे याचिका में बदलाव करना चाहती हैं, कोर्ट ने अनुमति दी

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख के एन्वायर्नमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वे याचिका में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर तक टाल दी। सिब्बल ने कहा कि वे याचिका में संशोधन के लिए आवेदन दायर करेंगे और हिरासत के आधार को चुनौती देंगे। सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने अनुरोध किया कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ नोट्स का लेने-देने की अनुमति दी जाए। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें वांगचुक के अपनी पत्नी के साथ नोट्स साझा करने में कोई समस्या नहीं है।

स्टेशन के साथ अब डाकघर से भी कटेगा टिकट, त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए नई सुविधा, जाने प्रक्रिया

नई दिल्ली, एजेंसी। दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान ट्रेन टिकटों के लिए परेशान रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए न तो लंबी लाइनों में लगने की जरूरत है और न ही स्टेशन तक जाने की। भारतीय डाक विभाग ने रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब लोग अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से ही ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य है कि गांव, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी टिकट बुकिंग की सुविधा आसानी से मिल सके, खासकर वहां जहां न तो रेलवे स्टेशन है और न ही आरक्षण काउंटर। यह नई व्यवस्था त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को संभालने और ग्रामीण इलाकों में यात्रा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

भारतीय डाक विभाग ने रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर देशभर के 333 पोस्ट ऑफिसों में टिकट बुकिंग सेवा शुरू की है। इनमें से ज्यादातर पोस्ट ऑफिस ग्रामीण और अर्ध-शहरी (सेमी-रूरल) इलाकों में स्थित हैं, ताकि दूर-दराज के लोगों को भी यह सुविधा आसानी से मिल सके। इन डाकघरों में पीआरएस टर्मिनल लगाए गए हैं, जिनके ज़रिए रेलवे टिकट बुक किए जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत यात्री सभी क्लास के टिकट स्लीपर, एसी, जनरल आदि बुक कर सकते हैं। यह पहल उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिन्हें अब टिकट बुकिंग के लिए शहरों या रेलवे काउंटर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दिल्ली : छात्रा का आरोप- यूनिवर्सिटी कैंपस में दबोचा, टी-शर्ट फाड़ी,पैंट उतारने की कोशिश

जबरदस्ती अबॉर्शन पिल खिलाई; FIR दर्ज, चारों आरोपी फरार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (SAU) की एक 18 साल की छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की घटना सामने आई है। हादसा 12 अक्टूबर की देर रात हुआ। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि चार आरोपियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में मुझे दबोच लिया और टी-शर्ट फाड़ दी। आरोपियों ने पैंट उतारने की भी कोशिश की।

पीड़ित ने जब खुद का बचाव किया तो आरोपी ने उसकी जांघ पर पैर रख दिया। फिर आंखों में उंगली डाल दी। एक आरोपी ने जबरदस्ती मुंह खोल दिया और अबॉर्शन पिल खिला दी। हालांकि दवाई खिलाने की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। वह 13 अक्टूबर की सुबह परिसर में घायल अवस्था में मिली थी। पीड़ित ने FIR दर्ज कराई है, चारों आरोपी फरार हैं।

क्या है मामला... युवती ने अपनी FIR में आरोप लगाया है कि घटना से कुछ दिन पहले आर्यन यश नाम के एक व्यक्ति ने उसे ईमेल और सोशल मीडिया पर अश्लील और धमकी भरे मैसेज भेजे थे। इसके बाद वॉट्सएप और टेलीग्राम पर भी मैसेज आने लगे, जिसमें भेजने वाले ने छात्रा की प्रोफाइल फोटो को एडिट करके न्यूड बनाकर धमकी दी कि अगर वह एक घंटे में यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर नहीं आई तो फोटो सभी छात्रों को भेज दी जाएगी।

संतरागाछी एक्सप्रेस में महिला से रेप, कोच में अकेली थी

गुंटूर स्टेशन पर महिला डिब्बे में जबरन घुसा आरोपी, चाकू दिखाकर धमकाया, मोबाइल-पैसे भी लूटे

अमरावती ,एजेंसी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और पेद्दाकुरापाडु रेलवे स्टेशनों के बीच एक पैसेंजर ट्रेन में महिला के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोपी ने चाकू दिखाकर महिला से रेप किया। उसने पीड़ित के 5500 से ज्यादा रुपए और फोन भी लूट लिया। घटना 13 अक्टूबर को हुई जब राजामहेंद्रवरम की रहने वाली महिला, यहा चरलापल्ली जाने के लिए संतरागाछी स्पेशल एक्सप्रेस में सवार हुई। पीड़ित, महिला कोच में थी और शुरुआत में अकेली यात्रा कर रही थी।

पीड़ित ने चरलापल्ली पहुंचकर दर्ज कराई FIR : ट्रेन, गुंटूर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो 40 साल का व्यक्ति कोच का दरवाजा खोलने लगा। पीड़ित ने बताया कि यह महिलाओं का डिब्बा है। इसके बाद महिला ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। लेकिन आरोपी ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मना लिया और डिब्बे में घुस गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। जब ट्रेन गुंटूर और पेद्दाकुरापाडु रेलवे स्टेशन के बीच थी, तो उस व्यक्ति ने चाकू दिखाकर धमकाया और उसके साथ रेप किया। जब ट्रेन पेद्दाकुरापाडु रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तो आरोपी उससे कूदकर भाग गया। महिला ने चरलापल्ली तक अपनी यात्रा जारी रखी और कानूनी कार्रवाई के लिए सिकंदराबाद स्टेट रेलवे पुलिस से संपर्क किया।

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध की शर्तों में ढील देते हुए 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की इजाजत दे दी है। केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध में राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सिर्फ नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के आदेश: अदालत ने शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। ये अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयमित रूप से इसकी अनुमति देनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने आदेश का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा, पटाखों की दिल्ली-एनसीआर में तस्करी की जाती है और वे ग्रीन पटाखों से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि (21 अक्टूबर) के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं नियमों के उल्लंघन करने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सुबह और रात के इस वक्त मिली अनुमति : सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, जो कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक जारी रहेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बाहर से पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट आदेश में कहा कि अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने और उसके समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

गश्ती दल गठित करने का आदेश : इतना ही नहीं गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को गश्ती दल गठित करने का आदेश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल क्यूआर कोड वाले अनुमत उत्पाद ही बेचे जाएं। ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। जिससे प्रमाणिकता की जांच की जा सकें। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ग्रीन पटाखों की बिक्री सिर्फ प्रमाणित कंपनियों की ओर से निर्धारित स्थानों से ही की जा सकेगी।

बिहार चुनाव : जेडीयू की पहली लिस्ट 57 कैंडिडेट्स के नाम

चिराग के दावे वाली 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे

बाहुबली-3, मुस्लिम- 0, 6 मंत्री मैदान में

पटना, एजेंसी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए JDU ने बुधवार को अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में JDU ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धुमल सिंह, कुचाएकोट से अमरेंद्र पांडेय को उतरा है। लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। 10 अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट्स को उतारा है। लिस्ट में 6 मंत्री भी हैं। 4 महिलाओं को भी टिकट मिला है। इसके अलावा चिराग के दावे वाली 5 सीटों सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा पर भी जेडीयू ने कैंडिडेट उतारे हैं। पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। 2 विधायकों का टिकट कटा है। सकरा से आदित्य कुमार और बरबीघा से सुदर्शन कुमार। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए अपनी सिटिंग सीट छोड़ दी है। पिछली बार तारापुर जेडीयू के खाते में थी। इस बार यहां से बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी लड़ेंगे। वहीं परबत्ता सीट भी JDU ने गठबंधन के लिए छोड़ी है। 2020 में परबत्ता जदयू के खाते में थी। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण ऊर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में JDU 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य पहले फेज के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे।

मंत्री विजय चौधरी के बेटे की जगह फिर उन्हें उतारा : सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे के चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मंत्री विजय चौधरी को ही उतारा है। मंत्री महेश्वर हजारी के टिकट कटने की चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। कल्याणपुर से टिकट दिया है। पार्टी ने मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा, मदन सहनी को बहादुरपुर, महेश्वर हजारी को कल्याणपुर और सुनील कुमार को भोरे, सोनबरसा से रत्नेश सदा को मैदान में उतारा है।

नीतीश के नेतृत्व में NDA लड़ेगा चुनाव- 2025 के चुनाव में NDA का साफ कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। शुरुआत में NDA में नीतीश को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब फिर बीजेपी के बड़े नेताओं ने नीतीश के चेहरे पर मुहर लगा दी। जेडीयू भी नीतीश को ही सीएम चेहरा मान रही है और उनका नारा है- '2025 से 2030, फिर से नीतीश।'

एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर, बोले- सब ठीक

अमित शाह से दिल्ली में 45 मिनट मुलाकात की; प्रशांत किशोर ने कहा- मैं चुनाव नहीं लडूंगा

नई दिल्ली/पटना, एजेंसी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA और महागठबंधन, दोनों गुटों में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी चल रही है। NDA में JDU और लोजपा (रामविलास) के बीच कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट लोजपा (आर) को देने की चर्चा से नाराज हैं।

कुशवाहा को मनाने के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मंगलवार देर रात पटना स्थित उनके आवास पहुंचे। रातभर माथापच्ची के बाद भी कुशवाहा नहीं मानें, तो दोनों भाजपा नेता चुपचाप चले गए। इसके बाद कुशवाहा ने कहा, "Nothing is well in NDA" (NDA में सबकुछ ठीक नहीं है)। इसके बाद अमित शाह ने कुशवाहा को फोन करके दिल्ली बुलाया। बुधवार को दोनों के बीच 45 मिनट बातचीत हुई। मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से कहा- सब ठीक है। हमारा गठबंधन बिहार चुनाव जीतेगा। दूसरी तरफ, प्रशांत किशोर ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। RJD चीफ लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया। लालू और राबड़ी भी तेजस्वी के साथ दिखे। वहीं, लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप ने आज अपना नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। वे अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट से नामांकन भरेंगे।

राजस्थान बस अग्निकांड में 21 मौत, पहली एफआईआर दर्ज

10 साल के बच्चे ने दम तोड़ा, अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर

जैसलमेर/जोधपुर, एजेंसी। राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड में हादसे के बाद मंगलवार देर रात पहली एफआईआर दर्ज हुई है। हादसे का शिकार पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज कराया है।

वहीं, अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। हादसे में झुलसे 10 साल के यूनुस ने भी सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।

इस बीच शवों की पहचान के लिए जोधपुर और जैसलमेर के हॉस्पिटल में डीएनए सैंपल लिए जा रहे है। सैंपल कलेक्शन के प्रोसेस में नाराजगी को लेकर हॉस्पिटल अधीक्षक ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा इस प्रक्रिया में वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है। जिससे कि कोई गलती न हो। उन्होंने बताया अधिकतम 24 घंटे में शवों की पहचान की प्रोसेस पूरी हो जाएगी।

दरअसल, मंगलवार दोपहर 3.30 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी। हादसे में मंगलवार को 20 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 19 मौत बस के अंदर और एक मौत जोधपुर के हॉस्पिटल में हुई थी

बस में पटाखे होने का अंदेशा

स्लीपर बस में आग लगने के कारणों को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे है। सबसे पहले बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई थी। इसके बाद एसी का कम्प्रेशर पाइप फटने से आग लगने का दावा था। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि बस की डिग्गी पटाखों से भरी थी, इस कारण आग भड़की।

मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50 हजार की मदद

जैसलमेर बस हादसे में प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने x पर पोस्ट की है, जिसमें लिखा- राजस्थान के जैसलमेर में हुई दुर्घटना से हुई जान-माल की हानि से मन व्यथित है।

मंत्री बोले- कुछ लोग खाक हो गए

गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया- पीछे से धमाके की आवाज आई। हमें लग रहा है एसी का कंप्रेशर फट गया। गैस और डीजल के साथ मिलकर बहुत भीषण आग लगी। एक ही दरवाजा था। इसलिए लोग फंस गए। आगे की सीट वाले निकल गए। बस से जो बॉडी निकाली जा सकीं, आर्मी ने निकाल लीं। जो बिल्कुल ही खाक हो गए, उनका कहा नहीं जा सकता।

हाईकोर्ट में कई मामलों में हुई सुनवाई, जानें केजरीवाल और 1984 दंगों से जुड़े मामले में क्या कहा

नई दिल्ली, एजेंसी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि उसके पास गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। यह फैसला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की याचिका पर आया, जिसमें संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यूएपीए ट्रिब्यूनल के कार्यों को सिविल कोर्ट के कार्यों के समान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पीएफआई की याचिका का जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया और पीएफआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को होगी। केंद्र सरकार ने पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों, जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल विमेंस फ्रंट आदि को सितंबर 2022 में यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। केंद्र ने आरोप लगाया था कि पीएफआई का आईएसआईएस से संबंध है और यह देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। केंद्र ने कोर्ट में दलील दी थी कि चूंकि यूएपीए ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता हाईकोर्ट के मौजूदा जज कर रहे हैं, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। ालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का आदेश सिविल कोर्ट के आदेश की तरह नहीं है, बल्कि यह केंद्र द्वारा की गई घोषणा को पुष्ट करने का कार्य करता है। कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के पास ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सर्टियोरारी रिट (निचली अदालतों या ट्रिब्यूनल के आदेशों को रद्द करने की शक्ति) जारी करने का अधिकार क्षेत्र है।

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई 6 नवंबर को: राउज एवेन्यू कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान गवाह अब्दुल वाहिद और केपी सिंह को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) जितेंद्र सिंह ने मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों को स्वीकार करते हुए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य दर्ज करने और गवाह केपी सिंह की चिकित्सा स्थिति पर सत्यापन रिपोर्ट के लिए 6 और 7 नवंबर की तारीख तय की है। कोर्ट में पेश हुए दस्तावेजों के अनुसार, पहले गवाह अब्दुल वाहिद को जारी समन उचित तामील रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि, सीबीआई की ओर से वरिष्ठ सरकारी वकील ने बताया कि वाहिद बुखार से पीड़ित होने के कारण अदालत में हाजिर नहीं हो सके। उनके वकील ने सहायक चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के साथ छूट का आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि गवाह अगली सुनवाई पर उपस्थित होंगे। न्यायाधीश ने इस आवेदन को मंजूर कर लिया और वाहिद को सुनवाई में पेश होने से छूट प्रदान की। गवाह केपी सिंह के मामले में भी समान स्थिति बनी। सिंह के वकील ने पूर्व आवेदनों का हवाला देते हुए दोहराया कि बुजुर्ग गवाह अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हैं। उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अदालत में गवाही देने की स्थिति में नहीं हैं। सीबीआई के वकील ने स्पष्ट करने के लिए समय मांगा कि क्या अभियोजन पक्ष को सिंह से पूछताछ की आवश्यकता है। कोर्ट ने मुख्य सूचना अधिकारी को निर्देश दिए ।

राजपाल को राहत, दुबई यात्रा की अनुमति

चेक बाउंस मामले में फंसे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने दीपावली समारोह में हिस्सा लेने के लिए दुबई जाने की मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की एकल पीठ ने राजपाल को कुछ शर्तों के साथ यह राहत प्रदान की, जिसमें एक लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) जमा करना और यात्रा के दौरान मोबाइल फोन चालू रखना शामिल है। अदालत ने आदेश दिया कि राजपाल यादव अपनी पत्नी का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमानत के रूप में जमा करेंगे। दुबई से लौटने के बाद राजपाल को अपना पासपोर्ट भी निचली अदालत में सौंपना होगा। अदालत ने साफ निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्रिय रहे, ताकि अदालती कार्यवाही पर असर न पड़े।

पैरोल आवेदनों में देरी पर राज्य गृह सचिव तलब

जेल प्रशासन की ओर से पैरोल आवेदनों पर बार-बार देरी करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्रधान सचिव (गृह) को तलब किया है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकारी अधिकारी कानून और जेल में बंद व्यक्तियों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने नाराजगी जताते हुए गृह सचिव को 6 नवंबर 2025 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।

पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुए हैं दाखिले

अब तक एक लाख दस हजार छात्रों ने प्रवेश सुनिश्चित किया

दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्नातक कार्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया पूरा करने का बुधवार आखिरी दिन है। इस बार पिछली वर्ष की तुलना में एसओएल में दाखिले को लेकर छात्रों के बीच अधिक उत्साह देखने को मिला। दाखिले के लिए पिछली बार से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण किया है। कैंपस ऑफ लर्निंग की निदेशक प्रो. पायल मागो ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए दो लाख 70 हजार के करीब छात्रों ने पंजीकरण किया है। इसमें अभी तक एक लाख दस हजार छात्रों ने दाखिला सुनिश्चित कर लिया है। पिछले वर्ष एक लाख सात हजार के करीब दाखिले हुए थे।

15 अक्तूबर तक फीस जमा कर सकते हैं छात्र : पंजीकरण और दाखिला सुनिश्चित के आंकड़ों में अंतर की वजह से छात्रों का रेगुलर कॉलेज में दाखिला लेना हो सकता एसओएल में दाखिला पंजीकरण की प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई। अब पंजीकरण करने वाले उम्मीदवार 15 अक्तूबर तक सिर्फ फीस का भुगतान कर दाखिला प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। उसके बाद दाखिला तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा। दाखिले का यह अंतिम मौका है। उन्होंने कहा कि एसओएल में 19 स्नातक कार्यक्रमों की पढ़ाई होती है। इस वर्ष बीबीए प्रोग्राम में दाखिले के लिए छात्रों का अच्छा रुझान देखने को मिला है।

सरकार की बड़ी पहल, जन्म-पेंशन सहित 50 से अधिक सेवाएं जल्द व्हाट्सएप पर होंगी उपलब्ध

नई दिल्ली, एजेंसी। जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, पेंशन स्थिति, कर भुगतान, शिकायत निवारण समेत 50 से अधिक सेवाओं का लाभ आप सीधे व्हाट्सएप के जरिये उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने 50 सेवाओं को हर मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल क्रांति की तैयारी शुरू की है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने व्हाट्स-एप गवर्नेंस सर्विसेज शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। यह परियोजना दिल्ली सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। विभाग का उद्देश्य नागरिकों को 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही कागजी जंजाल और लंबी कतारें इतिहास बन जाएं। योजना के तहत चयनित एजेंसी व्हाट्स एप बिजनेस एपीआई और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक उन्नत मल्टीलिंगुअल चैटबॉट सिस्टम तैयार करेगी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा। यह सिस्टम दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और अन्य विभागीय पोर्टलों से जुड़ा रहेगा। प्रारंभिक चरण में 50 सेवाएं शामिल की जाएंगी, जिन्हें बाद में सभी विभागों तक विस्तारित भी किया जाएगा।

तकनीक और सुरक्षा होंगे मजबूत : परियोजना आईटी अधिनियम 2000 और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी। सभी डेटा राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) के अनुमोदित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सरकार तीन साल के एक निजी एजेंसी को काम देगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार अब सेवाएं जनता की उंगलियों पर होंगी।

नेतन्याहू मिले रिहा बंधकों से, एतान मोर से छूटने की वजह जानकर चौंके

तेल अवीव, एजेंसी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास की कैद से छूटे बंधकों से मिलकर उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को यहां बेइलिन्सन अस्पताल में रिहा हुए बंधकों और उनके परिवारों से मुलाकात कर चर्चा की। सोमवार को रिहा किए बंधक एतन मोर की आपबीती सुनकर प्रधानमंत्री ही नहीं अन्य लोग भी चौंक गए। मोर ने बताया कि गाजा में कैद के दौरान एक हमास नेता ने उससे कहा था कि उसके रिहा होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसके परिवार ने सरकार पर बंधक-युद्धविराम समझौते के लिए दबाव डालने वाले विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लिया।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार, मोर ने प्रधानमंत्री को बताया कि इज्ज अल-दीन अल-हद्दाद इस समय आतंकवादी समूह हमास का वास्तविक नेता है। वह पहले हमास के गाजा सिटी ब्रिगेड की कमान संभालता रहा है। इसी नेता ने उससे कैद के दौरान कहा था, अगर किसी को सबसे पहले रिहा किया जाएगा, तो वो आप हैं। आपके पिता वैसे भी विरोध प्रदर्शनों में नहीं जाते, इसलिए हम आपको पहले वापस भेज देंगे। मोर के पिता ज्विका टिकवा फोरम के प्रमुख हैं। यह फोरम बंधक परिवारों का छोटा समूह है। यह फोरम पहले के उन समझौतों का विरोध करता रहा है, जिनमें सैकड़ों फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और गाजा में अस्थायी युद्धविराम के बदले में केवल कुछ बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की गई थी।

इस बीच बंधक परिवारों ने शव सौंपने में हमास की विफलता पर आईडीएफ प्रमुख से मुलाकात की मांग की है। बंधक और लापता परिवार मंच ने कहा है कि वह आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर से बात करना चाहते हैं। मंच ने बयान में कहा है, परिवार चीफ ऑफ स्टाफ से इस बात का स्पष्टीकरण मांगेंगे कि आईडीएफ समझौते का सामान्य रूप से पालन क्यों कर रहा है, जबकि इस बात की गंभीर आशंका है कि बंधक कैद में ही रहेंगे क्योंकि हमास हस्ताक्षरित समझौते का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है।

परिवारों का आरोप है कि आईडीएफ अभी भी 7 अक्टूबर, 2023 के नरसंहार से पहले की तरह ही व्यवहार कर रहा है। हमास की बातों पर विश्वास कर रहा है। बजाय इसके कि वह यह समझे कि यह एक धोखेबाज और घृणित आतंकवादी संगठन है।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउवा लेंगे सक्रिय राजनीति से संन्यास, इलाज के लिए सिंगापुर जाने की तैयारी

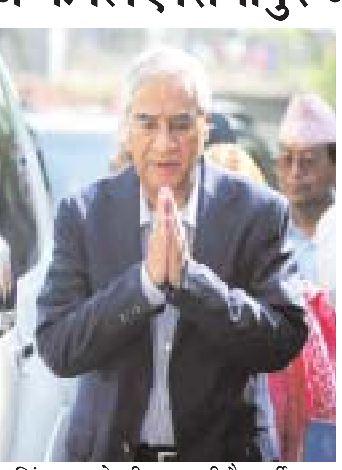

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा पार्टी की सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हुए इलाज के लिए सिंगापुर जाने की तैयारी में हैं। पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में एक लिखित वक्तव्य पढ़ते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी । जेन जी विद्रोह के दौरान बुरी तरह से घायल हुए नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा 35 दिन बाद मंगलवार को अपने पार्टी के दफ्तर में आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक में सहभागी हुए। उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड़का को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सौंपने का फैसला किया है। देउवा ने कहा कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही अब समय पर महाधिवेशन के बाद नए नेतृत्व का चयन हो जाए, इसके लिए सभी को तैयारी करनी होगी। देउवा ने महाधिवेशन के बाद निर्वाचित नए अध्यक्ष को पार्टी का नेतृत्व हस्तांतरण कर देंगे।

देउवा ने अब राजनीति में सक्रिय नहीं रहने का संकेत देने के साथ ही अपने उपचार के लिए सिंगापुर जाने की बात कही है। पार्टी बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत अधिक देर तक बैठने पर उन्हें चक्कर आने लगता है और बेहोशी छाने लगती है। जेन जी विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में घुस कर शेरबहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू देउवा पर हमले किए थे। इस दौरान उन पर खुकरी से भी हमला किया गया जिसके कारण शेर बहादुर देउवा के माथे पर 12 टांके और आरजू देउवा के गर्दन पर 8 टांके लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पूरा उन का घर जला दिया था। ड्डइस घटना के ंगापुर जाने की बात कही है।

शेष मृत बंधकों के बारे में खबर जल्द मिलने की उम्मीद: नेतन्याहू

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि गाजा में शेष मृत बंधकों के बारे में कुछ घंटों में जानकारी मिलने की उम्मीद है। नेतन्याहू ने केंद्रीय इजराइल के एक ही उम्मीद है कुछ घंटों में अतिरिक्त मारे गए बंधकों की वापसी को लेकर समाचार मिलेंगे। लेकिन हमारा संकल्प है कि हर एक को वापस लाया जाएगा। इजराइल ने मारे गए बंधकों के शवों की वापसी में देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंगरवार को गाजा में भेजी जाने वाली मानवीय सहायता को आधा कर दिया है ।

जापान में एलडीपी को इशिबा के उत्तराधिकारी के चुनाव में झटका देने की तैयारी में विपक्ष

टोक्यो, एजेंसी। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को निवर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के उत्तराधिकारी के चुनाव में संसद (डाइट) में झटका लग सकता है। एलडीपी अगले प्रधानमंत्री के चयन के लिए 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान की अंतिम तैयारी में जुटी है। एलडीपी संसद के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) और पार्षद सदन (ऊपरी सदन) में सबसे बड़ी पार्टी है पर संख्या बल में कमजोर है। विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी को पटखनी देने के लिए गुणा-भाग कर रहा है। जापान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार संसद में मतदान इसी सप्ताह निर्धारित था। अब मतदान संसद सत्र के पहले दिन होने की उम्मीद है। इस बात की संभावना है कि नई अध्यक्ष साने ताकाइची के नेतृत्व वाली एलडीपी और जापान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कॉन्स्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीपी) के बीच गठबंधन हो सकता है।

चार अक्टूबर को ताकाइची के अध्यक्ष निर्वाचित होने का बाद गठबंधन में सहयोगी कोमेइतो पार्टी ने सत्तारूढ़ गुट से बाहर होने की घोषणा की है। एलडीपी संसद के दोनों सदनों में सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किसी में भी बहुमत नहीं है। इसलिए कट्टर रूढ़िवादी और पूर्व मंत्री ताकाइची के जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुने जाने की संभावना अभी भी अस्पष्ट है। सीडीपी के प्रमुख योशीहिको नोडा ने कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल (डीपीपी) के नेता युइचिरो तामाकी का समर्थन करना एक विकल्प हो सकता है। द जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार निचले सदन में बहुमत पाने वाला सांसद ही प्रधानमंत्री बनेगा। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो दो शीर्ष दावेदारों के बीच मुकाबला होगा। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति निर्वाचित होगा। सीडीपी, डीपीपी और निप्पॉन इशिन नो काई को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों पार्टियों की प्रमुख नीतियों और राजनीतिक उद्देश्यों के मामले में काफी अंतर है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें एकता होगी या नहीं।

विपक्षी दलों ने मंगलवार को संभावित सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संसद में कई बैठकें कीं। डीपीपी ने पहले एलडीपी के साथ बैठक की। डीडीपी ने ताकाइची को प्रधानमंत्री चुनने के लिए समर्थन मांगा। डीपीपी महासचिव काज़ुया शिम्बा ने अपने एलडीपी समकक्ष शुनिची सुजुकी से आग्रह किया कि वे आयकर छूट की सीमा बढ़ाने और अस्थायी गैसोलीन कर को समाप्त करने के लिए दोनों दलों के बीच हुए समझौते का सम्मान करें। शिम्बा ने पार्टी के गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होने से इनकार करने की बात दोहराई। शिम्बा ने बाद में कोमेइतो के महासचिव मकोतो निशिदा से भी मुलाकात की। इसके बाद डीपीपी महासचिव ने सीडीपी और निप्पॉन इशिन में अपने समकक्षों के साथ बैठक की। शिम्बा ने सीडीपी पर सुरक्षा, ऊर्जा और संविधान पर अपना रुख स्पष्ट करने का दबाव डाला। उन्होने कहा कि उनके निप्पॉन इशिन समकक्ष हिरोशी नाकात्सुका ने भी उनकी भावनाओं का समर्थन किया।

नरेला की कार्डबोर्ड फैक्टरी में भीषण आग, दमकल विभाग की 26 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के नरेला स्थित भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में बुधवार को एक कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल सामने नहीं आई है। अग्निशमन अधिकारी एस.के. दुआ ने बताया, ÷दिल्ली अग्निशमन सेवा को नरेला के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्टरी में आग लगने की घटना के बारे में सूचना मिली। मौके पर दमकल की 26 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है।÷

सीबीआई ने एनएचआईडीसीएल के अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के गुवाहाटी कार्यालय के कार्यकारी निदेशक और क्षेत्रीय अधिकारी मैसनम रितेन कुमार सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उनके साथ एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि बिनोद कुमार जैन को भी पकड़ा है। सीबीआई के मुताबिक, एजेंसी ने 14 अक्टूबर को जाल बिछाकर दोनों को 10 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह रिश्वत असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के डेमो से मोरान बाइपास तक के चार लेन निर्माण कार्य में समय बढ़ाने और काम पूरा होने का प्रमाण पत्र देने के लिए मांगी गई थी। सीबीआई ने आरोपियों के सात ठिकानों पर छापा मारा और वहां से 2.62 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। जांच में पता चला है कि अधिकारी और उनके परिवार के नाम देश के कई हिस्सों में 9 जमीन के टुकड़े और 20 फ्लैट हैं। साथ ही कई महंगी गाड़ियों के दस्तावेज भी मिले हैं। सीबीआई अभी भी मामले की जांच कर रही है। दोनों आरोपितों को आज गुवाहाटी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

मतदाता प्रलोभन पर होगी सख्ती, एजेंसियों को चुनाव आयोग के कड़े निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और देश के अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे, शराब, नशीले पदार्थ या मुफ्त उपहार देने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए देश की एजेंसियों को इसे रोकने के लिए आदेश जारी किया है। आयोग ने बताया कि इस संबंध में राज्य की सभी जांच और प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। आयोग ने इसके लिए पुलिस विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, आयकर विभाग, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू-इंड), आरबीआई, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), केंद्रीय और राज्य जीएसटी विभाग, सीमा शुल्क, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), डाक विभाग, राज्य वन विभाग और राज्य सहकारी विभाग को निर्देशित किया है। आयोग ने बताया कि चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षक पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। ये अधिकारी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचकर उड़न दस्तों, निगरानी टीमों और वीडियो निगरानी दलों के साथ तालमेल से काम कर रहे हैं। इन सभी इकाइयों को 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या प्रलोभन की कोशिशों को समय रहते रोका जा सके। चुनाव आयोग ने जब्ती से जुड़ी कार्रवाई को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए इस बार एक ऑनलाइन प्रणाली चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) भी शुरू की है। इसके माध्यम से एजेंसियां जब्त की गई नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री की जानकारी तुरंत ऑनलाइन भेज रही हैं। उल्लेखनीय है कि 6 अक्तूबर 2025 को चुनावों की घोषणा के बाद से अब तक विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कुल 33.97 करोड़ रुपये की नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त उपहार जब्त किए जा चुके हैं।

परिचित ने घर बुलाकर मोबाइल लूटा

नई दिल्ली एजेंसी । छावला इलाके में एक व्यक्ति ने अपने परिचित को घर बुलाकर मोबाइल लूट लिया। जानकारी के अनुसार, रोहन लांबा (28), रोशनपुरा, नजफगढ़ में परिवार के साथ रहता है और गोयला डायरी में वेल्डिंग मिस्त्री का काम करता है। उसके परिचित जितेंद्र ने 12 अक्टूबर को घर पर कुछ काम के बहाने बुलाया। वहां जितेंद्र एक अन्य युवक के साथ मौजूद था। बातचीत के दौरान जितेंद्र ने रोहन का मोबाइल देखा और उसे देने को कहा। रोहन के इन्कार करने पर जितेंद्र ने लाठी-डंडे से हमला कर पिटाई की, और साथी के साथ मिलकर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया। घायल रोहन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। छावला थाना पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया है और भागे हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है।

जिंदा अपराधी की फर्जी मौत, जाली प्रमाण पत्र पर थे पूर्व पार्षद के साइन, 14 दिन में बताए पुलिस

दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी आरोपी वीरेंद्र विमल का जाली मृत्यु प्रमाण पर कैसे बना अब यह सवाल रोहिणी कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सार्थक पंवार ने पुलिस से पूछा है। दिल्ली पुलिस के बवाना थानाध्यक्ष को इस मामले की जांच करने और इसकी रिपोर्ट 14 दिनों में दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने दिल्ली नगर निगम से वर्ष 2021 में जाली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था। आरोपी बदमाश वीरेंद्र विमल ने जाली मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो एप्लीकेशन दी थी उस पर बवाना की पूर्व निगम पार्षद पूनम के हस्ताक्षर थे। हालांकि सीनियर पुलिस अधिकारी ने हस्ताक्षर के असली-नकली होने की पुष्टि नहीं की और इसे जांच का विषय बताया।पूर्व निगम पार्षद के पति पवन सेहरावत (बवाना से वर्तमान में निगम पार्षद) ने अमर उजाला को बताया कि उनकी पत्नी के हस्ताक्षर नहीं है। वह निर्दलीय चुनाव जीती थीं और बाद में भाजपा में शामिल हो गई थीं। वह वर्ष 2021 तक निगम पार्षद थीं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य समयसीमा में पूर्ण करें : प्रेक्षक के.पी. पाण्डेय

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक के.पी. पाण्डेय (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.) द्वारा बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

प्रेक्षक पाण्डेय ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 08 अक्टूबर को प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। प्राधिकृत कर्मचारी 17 अक्टूबर 2025 की अपरान्ह 3 बजे तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करेंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समयसीमा में पूर्ण किया जाए। प्रेक्षक ने बताया कि उनके द्वारा कुछ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ स्थानों पर कार्य संतोषजनक पाया गया, जबकि कुछ स्थानों पर सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रेक्षक पाण्डेय ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सतत सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की आयु 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराए जाएं। साथ ही अशुद्ध रूप से दर्ज नामों के सुधार, मृतक अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के कार्य में भी पारदर्शिता रखी जाए। उन्होंने बीएलए के माध्यम से इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने पर बल दिया।

बैठक में उपखंड अधिकारी गोपद बनास राकेश शुक्ला, सिहावल प्रिया पाठक, मझौली आर.पी. त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी, भाजपा से अमित प्रधान, कांग्रेस से अखंड प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सड़क सुरक्षा पर मुख्यमंत्री का जोर, नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जीवन अनमोल है और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का पालन अनिवार्य रूप से करें। मुख्यमंत्री ने आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एडवांस एप्लीकेशन 'संजय' का शुभारंभ किया और आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार ''सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रणाली'' पुस्तक एवं श्रोड सेफ्टीश् रिपोर्ट का विमोचन किया।

कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग एवं मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने आईआईटी मद्रास और सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ डीडीएचआई और सड़क सुरक्षा प्रबंधन पर दो एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन-जागरूकता, तकनीकी सुधार और सामूहिक सजगता जरूरी है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विभाग ने लोकपथ ऐप और ब्लैक स्पॉट अलर्ट सिस्टम जैसी पहल की है, जिससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट की सही उपयोगिता से अधिकतर जानें बचाई जा सकती हैं।

आईआईटी मद्रास के प्रो. वेंकटेश बालासुब्रमण्यम ने सड़क सुरक्षा के लिए साझा डेटा और वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1041 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और सुधार कार्य लगातार जारी हैं। कार्यशाला में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने एनआईसी केंद्र सीधी से वर्चुअली सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि सड़क सुरक्षा को केवल नियम नहीं बल्कि संस्कृति बनाएं और जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चलाएं।

दिव्यांग बच्चों की पहचान हेतु शिविर का हो रहा आयोजन, कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर गठित किशोर न्याय समिति के परिपालन में जिले के 0 से 18 वर्ष आयु समूह के दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान एवं त्वरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार जिले में 29 सितंबर से 14 नवंबर तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर मुख्यालयों पर तथा नगरीय क्षेत्रों में जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

कलेक्टर ने कड़े निर्देश दिए हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सीधी शिविरों में सभी विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करें। यह संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर चिकित्सक दल शिविरों में नियत समय तक उपस्थित नहीं रहते, जो कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है। इस पर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय) जिला सीधी के पत्र दिनांक 22 सितंबर 2025 के अनुसार शिविर कार्य हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यदायित्व सौंपा गया है। सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी अपने सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करें और शिविर के दिवस पर प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। कलेक्टर ने कहा कि शिविरों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुपस्थित पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पंजीयन एवं धान खरीदी में अधिकारियों के भ्रष्टाचार का विधायक ने खोला पोल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले के सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने 14 अक्टूबर 2025 को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कलेक्टर रीवा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि खाद्य विभाग, वेयरहाउस, सहकारी बैंक और नान अधिकारियों के द्वारा किसानों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

प्रेस वार्ता के दौरान विधायक अभय मिश्रा ने बताया कि धान खरीदी और किसानों के पंजीयन में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति प्रबंधकों द्वारा सिकमी में फर्जी पंजीयन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की वास्तविक जानकारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन खरीदी केंद्रों को पहले ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उन्हें फिर से धान खरीदी का काम सौंपा गया है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। अभय मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष धान पंजीयन में

6785 फर्जी किसानों का पंजीयन किया गया है, जिनके पास जमीन नहीं है। यह स्थिति न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष फर्जी किसानों के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपये की धान बिक्री का मामला भी सामने आया है, लेकिन किसानों को आज तक पैसा नहीं मिला है।

किसान अब धान की रसीद लेकर समितियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस पूरे फर्जीवाड़े के लिए विधायक ने जिला कलेक्टर, सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडेय, वेयरहाउसिंग जिला मैनेजर केबी बागरी, कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी विनीत मिश्रा और नान ऑपरेटर संजय यादव, खाद्य विभाग के फूड ऑपरेटर शिव पूजन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पूर्व में भी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और विधानसभा में भी सवाल उठाया है, लेकिन अधिकारियों ने झूठी जानकारी देकर खुद को बचा लिया है।

अभय मिश्रा ने शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा कि किसी भी विभाग में कोई अधिकारी कर्मचारी 3 या 4 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता है, लेकिन 48 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी रीवा जिला सहकारी बैंक में 6 साल से पदस्थ हैं। इसी तरह से वेयरहाउस प्रबंधक केबी बागरी 10 वर्ष से पदस्थ हैं, लेकिन इनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है।

विधायक ने कहा कि यह सब अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि खाद्य विभाग में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर शिव पूजन सिंह की भूमिका भी संदिग्ध है। उनके द्वारा किसानों से मोबाइल नंबर सुधारने के नाम पर वसूली की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान अमरेश कुमार द्विवेदी उर्फ मिंटू परीहा ने कहा कि जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडेय के सह पर धान पंजीयन केंद्रों में जमकर वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वयं के पंजीयन के नाम पर और अधिया-बटाई के सिकमी पंजीयन के नाम पर 2000 से 3000 रुपये वसूले जा रहे हैं, जिसका हिस्सा महाप्रबंधक तक पहुंचता है।

युवा उत्सव से कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है : डॉ. आई.पी. प्रजापति

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय महाविद्यालय मड़वास में म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार त्रिदिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ युवा उत्सव के संयोजक डॉ. दीपक अग्निहोत्री ने किया। प्रथम दिवस के कार्यक्रम की प्रभारी डॉ. ज्योति रजक थीं, जिसमें समूह गान प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। द्वितीय दिवस के संयोजक प्रो. बाबा हरिनन्द थे, इस दिन स्पॉट पेंटिंग, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। तृतीय दिवस की प्रभारी डॉ. सौरभी गुप्ता और डॉ. संध्या वर्मा थीं, जिसमें समूह नृत्य, वाद-विवाद, वक्तृत्व और प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं सम्पन्न हुईं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पवन मिश्रा (जनभागीदारी अध्यक्ष) ने कहा कि युवा उत्सव छात्रों की प्रतिभा निखारने का उत्कृष्ट माध्यम है। विशिष्ट अतिथि शैलेन्द्र सिंह (प्रभारी प्राचार्य पथरौला स्कूल) ने कहा कि छात्र जीवन में सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, तभी सफलता प्राप्त होती है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आई.पी. प्रजापति ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि युवा उत्सव से कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दीपक अग्निहोत्री ने किया और आभार प्रदर्शन डॉ. आकांक्षा मिश्रा ने किया। त्रिदिवसीय युवा उत्सव में महाविद्यालय परिवार के सदस्य प्रो. प्रवीण कुमार, डॉ. निशा सिंह, डॉ. अमिता खरे, डॉ. सौरभी गुप्ता, डॉ. सुरेंद्र गुप्ता, डॉ. राजेश पटेल, डॉ. रामधारी जायसवाल, अनिल केवट और छात्र/छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी की।

केसलार स्कूल प्रभारी प्राचार्य के मनमानी रवैये से अव्यवस्था का आलम, बच्चों की पढ़ाई हो रही चौपट

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला अंतर्गत कुशमी विकासखंड के शा. हाई स्कूल केसलार के प्रभारी प्राचार्य रामलल्लू पनिका के मनमानी और अनियमितता की आए दिन खबरें सामने आती रहती हैं। आरोप है कि प्राचार्य नियमित स्कूल नहीं आते हैं और जब भी आते हैं, हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। जब उन्हें जानकारी होती है कि कोई अधिकारी जांच करने आने वाला है, तभी वे स्कूल में रहते हैं, जबकि उनका घर स्कूल से मात्र 7 किलोमीटर दूर है।

प्रभारी प्राचार्य की पदस्थापना के बाद से स्कूल की व्यवस्था बेकार हो गई है। अव्यवस्था का आलम बना हुआ है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनके कार्यकाल में स्कूल का स्तर न के बराबर हो गया है, जिसकी तुलना पूर्व के परीक्षा परिणामों से की जा सकती है। इस स्थिति को लेकर समाजसेवियों और अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है।

कई बार विकासखंड अधिकारी कुशमी से शिकायत की गई है और इन्हें हटाने के लिए सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बताया जाता है कि प्राचार्य के परिवार का एक शिक्षक पवन पनिका भी है, जो कभी-कभी आते हैं। पिछले माह तो वे 13 दिन नहीं आए और इस माह भी उनकी उपस्थिति कम है। स्कूल में मध्यान्ह भोजन भी कभी मीनू के अनुसार नहीं बनता है। आरोप है कि प्राचार्य समूह वाले से चावल और नजराना लेते हैं, जिससे मीनू के अनुसार भोजन नहीं बनता।

स्कूल के शौचालय की सफाई भी कभी नहीं होती, जिससे गंदगी बनी रहती है। शिकायतकर्ता रायभान सिंह ने आरोप लगाए हैं कि एक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति में भी रुपये लिए गए हैं। वहीं, स्कूल में अरविंद साहू मंगलवार और गुरुवार को 1 बजे ही स्कूल से चला जाता है।

आरएसएस ने 2 किमी निकाला पथ संचलन, शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम; 270 स्वयंसेवक शामिल हुए

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सीधी जिले के हनुमानगढ़ में बुधवार को पथ संचलन निकाला गया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में अनुशासित भागीदारी की, जिसने समाज में एकता और संगठन का संदेश दिया। संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह संचलन ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ से शुरू हुआ। यह आदिवासी बस्ती, मुख्य बाजार और विद्यालय परिसर से होते हुए वापस ग्राम केंद्र पहुंचा, जहां लगभग 2 किलोमीटर की रैली निकाली गई। इस आयोजन में 270 स्वयंसेवक शामिल हुए।

स्वयंसेवकों ने अनुशासित पंक्तियों में कदमताल करते हुए राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। उनके अनुशासन और संगठन के प्रदर्शन ने ग्रामवासियों को प्रभावित किया। पूरा क्षेत्र भगवा ध्वज और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ग्रामवासी और बच्चों ने रास्ते के किनारे खड़े होकर स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया।

संगठन और समरसता का संदेश: इस कार्यक्रम का नेतृत्व खंड कार्यवाह रामनिवास सोनी ने किया। उन्होंने बताया कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी दिनों में पूरे खंड क्षेत्र में इसी तरह के पथ संचलन आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता, संगठन और सेवा की भावना को मजबूत करना है। पथ संचलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी सेमरिया और चौकी प्रभारी खड्डी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने पूरे मार्ग पर व्यवस्था बनाए रखी, जिसके कारण यह संचलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक और अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। स्थानीय नागरिकों ने भी इस आयोजन में सक्रिय सहयोग दिया।

ऋषियों द्वारा अमूल्य उपहार-दीपावली

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। पूज्यपाद संत आशाराम बापू अहमदाबाद द्वारा संचालित श्री योग वेदान्त सेवा समिति के वरिष्ठ साधक नानूभाई छप्पन भोग वाले ने बताया कि इस साल भी शास्त्री नगर, सिंधी धर्मशाला में हुई। जिसकी अध्यक्षता कैलाश आहूजा ने की। वरिष्ठ साधक भाई ने बताया कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाया जायेगा। 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन सुबह 8 बजे आरती, भजन, कीर्तन के बाद, फल व मिठाई वितरण किया जायेगा। गरीबों में फल, मिठाई का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। पूज्यपाद संत आशाराम बापू का वीडियों द्वारा बताया गया।

दीपावली सामाजिक, नैतिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ-साथ आत्मोन्नति कराने वाला उत्सव है। यह प्रकाश का उत्सव हमें आत्मप्रकाश की ओर ले जाने वाला है। यह हमारे सुख, ज्ञान तथा आनंद की वृद्धि के लिए, हमारी संस्कृति की शाष्वता की खबर दिलाने के लिये हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। दीपावली पर्व एक साथ 5 पर्वो की लड़ी है, जिसमें पहला पर्व धन त्रयोदशी है। इस दिन स्वास्थ्य की कामना से भगवान धन्वतरि की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी यमराज को तर्पण करने का पर्व है। अमावस्या की रात्रि में दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपावली की रात को लक्ष्मी जी व गणेश जी की संयुक्त पूजा का विधान है।

मझौली में एक दिवसीय अल्पविराम कार्यशाला का आयोजन

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। राज्य आनंद संस्थान एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मझौली विकासखंड के जनपद पंचायत परिसर प्रज्ञा भवन में एक दिवसीय अल्पविराम कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें शासी निकाय सदस्य कृष्णकांत द्विवेदी, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनैना सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश पाण्डेय, कार्यक्रम समन्वयक एवं मास्टर ट्रेनर राज्य आनंद संस्थान शिवदत्त उर्मलिया और डॉ. संजय श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि कृष्णकांत द्विवेदी ने बताया कि आनंद की संतुष्टि आपसी भाईचारे और संबंधों से मिलती है, जबकि अखिलेश पाण्डेय ने कहा कि आनंद बांटने से प्राप्त होता है और यह दीन-दुखियों की सेवा से बढ़ता है। कार्यशाला को पांच सत्रों में आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में प्रतिभागियों का परिचय और कार्यक्रम समन्वयक शिवदत्त उर्मलिया द्वारा स्वागत उद्बोधन एवं आनंद संस्थान का परिचय कराया गया। द्वितीय सत्र में मास्टर ट्रेनर द्वारा आनंद की ओर विषय पर सत्र लिया गया, जिसमें प्रतिभागियों से चर्चा कर यह समझाया गया कि आनंद लक्ष्य प्राप्ति पर आधारित होता है और निष्ठा पूर्वक कार्य न करने पर आनंद घटता है। अंतिम सत्र में जीवन का लेखा जोखा विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया और प्रमाण पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन रजनीश मिश्रा ने किया और आभार प्रदर्शन रजनीश द्विवेदी द्वारा किया गया।

खनिज विभाग की सघन जांच में जेसीबी व दो ट्रैक्टर जब्त

सीधी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीधी राकेश शुक्ला और जिला खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में गत दिवस खनिज विभाग द्वारा गोपदबनास क्षेत्र में खनिज अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सघन जांच की गई।

खनिज निरीक्षक शिशिर यादव के नेतृत्व में विभागीय खनिज अमले और पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम मड़वा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी में जांच की गई।

नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में सम्मान, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में मिला चौथा स्थान

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। भोपाल में आयोजित एक राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में सिंगरौली नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा रविंद्र भवन में प्रदान किया गया।

नगर निगम सिंगरौली ने स्वच्छ शहर (50 हजार से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी) में चौथा स्थान हासिल किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगर निगम सिंगरौली को सम्मानित किया।

सिंगरौली नगर निगम की ओर से नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय, उपायुक्त आर.पी. बैस और स्वच्छता टीम ने

यह सम्मान ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर सिंगरौली नगर निगम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिंगरौली ने स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है और टीम को भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने के लिए शुभकामनाएँ दीं।

सम्मान मिलने के बाद में बातचीत करते हुए नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान ने कहा कि हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि हम बेहतर से बेहतर करें सम्मान बताता है कि हमने बेहतर करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है नगर निगम का पूरा अमला और जनप्रतिनिधि मिलकर सिंगरौली को स्वच्छ सिंगरौली बनाने का प्रयास जारी रहेगा।

न्याय और न्यायाधिकरण, एआई से कामकाज पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनेगा

संपादकीय

न्यायाधिकरण अपना काम समय पर सही तरह इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें स्टाफ का अभाव है और जो है भी, वह उस विशेषज्ञता से लैस नहीं, जो आवश्यक है। न्यायाधिकरणों के फैसलों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। एक समस्या यह भी है कि न्यायाधिकरण के जज और वकील अपना काम तत्परता से नहीं करते।

विभिन्न न्यायाधिकरणों में अटके मामलों और उनसे हो रहे आर्थिक नुकसान के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार न्यायाधिकरणों में 3.56 लाख मामले अटके हैं। इसके चलते 24.72 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। यह राशि जीडीपी का 7.48 प्रतिशत है। न्यायाधिकरणों की न्याय प्रणाली निराश करने वाली ही नहीं, देश के आर्थिक विकास की राह रोकने वाली भी है।

यह एक विडंबना ही है कि न तो न्यायालयों में अटके पड़े करोड़ों लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए कुछ ठोस किया जा रहा है और न ही न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए। न्यायिक क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर बल तो सभी देते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए कोई आगे नहीं दिखता। यह स्थिति न्यायिक तंत्र के प्रति आस्था को डिगाने वाली है।

न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों का विवरण देने वाले थिंक टैंक दक्ष की रपट एक तरह से यही कहती है कि जिन उद्देश्यों के लिए इनका गठन किया गया, वे उसी काम को नहीं कर पा रहे हैं। वे न तो अदालतों का बोझ कम कर पा रहे हैं और न ही आर्थिक प्रशासन में निवेशकों का भरोसा बढ़ा पा रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि इससे विदेशी निवेश पर भी असर पड़ रहा होगा। न्यायाधिकरण अपना काम समय पर सही तरह इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें स्टाफ का अभाव है और जो है भी, वह उस विशेषज्ञता से लैस नहीं, जो आवश्यक है। न्यायाधिकरणों के फैसलों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। एक समस्या यह भी है कि न्यायाधिकरण के जज और वकील अपना काम तत्परता से नहीं करते। न्यायाधिकरणों को समय पर फैसला देने के लिए जवाबदेह बनाने की कोई ठोस व्यवस्था बनाना समय की मांग है। कहने को तो नेशनल कंपनी ला न्यायाधिकरण में किसी विवाद को निपटाने की समय सीमा 330 दिन है, पर वहां एक मामला निपटने में औसतन 752 दिन लगते हैं। यही स्थिति अन्य न्यायाधिकरणों की है। यदि आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रहे नीति-नियंता न्यायाधिकरणों के ढीले और समय खपाऊ कामकाज को लेकर चिंतित नहीं तो वे देश का अहित ही कर रहे हैं।

जब अनाज के ढेर में छुप जाए इंसान की भूख

दिलीप कुमार पाठक

विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2025)

विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाते दशकों हो चुके हैं, परंतु दुनिया भर में भूखे पेट सोने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। यह संख्या आज भी तेज़ी से बढती जा रही है। विश्व में आज भी कई लोग ऐसे हैं, जो भूखमरी से जूझ रहे हैं। इस मामले में विकासशील या विकसित देशों में किसी तरह का कोई फ़र्क़ नहीं है। विश्व की आबादी वर्ष 2050 तक नौ अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें क़रीब 80 फीसदी लोग विकासशील देशों में रहेंगे। ऐसे में किस तरह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। दुनिया में एक तरफ़ तो ऐसे लोग हैं, जिनके घर में खाना खूब बर्बाद होता है और फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जिन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता। खाद्यान्न की इसी समस्या को देखते हुए 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व खाद्य दिवस का मकसद दुनिया से भूखमरी खत्म करना है। आज भी करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मज़बूर हैं द्य हमें आधुनिक तरीके से खेती करनी होगी ताकि ज्यादा अनाज पैदा हो। इस दिन का उद्देश्य विकासशील देशों में तकनीकी और वित्तीय मदद बढ़ाना है ताकि वे ज्यादा अनाज उगा सकें।अफ्रीका के कई देशों में यह समस्या बहुत गंभीर है, जैसे रवांडा, बुरुंडी, नाइजीरिया और सोमालिया। हमें इन देशों की मदद करनी होगी ताकि वे अपने लोगों को खाना दे सकें। भूख और कुपोषण मुक्त दुनिया के सपने को साकार करने में हम सभी की भूमिका है। हमें संकट के समय में स्थायी आदतों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। हम स्वस्थ भोजन के विकल्प चुन सकते हैं और भोजन की बर्बादी को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, सरकारें, उद्यम और संगठन एवं अपनी समझ को साझा कर सकते हैं और स्थायी, लचीली खाद्य प्रणालियों और आजीविकाओं का समर्थन कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने विश्व का विकास, पोषण और स्थायित्व कर सकते हैं।

कुछ जगहों पर, खाद्य असुरक्षा की गंभीरता बहुत ज़्यादा है। अनुमान है कि 67.3 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ, मोटापे का बढ़ता स्तर और व्यापक खाद्य अपव्यय एक असंतुलित व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं द्य बढ़ती वैश्विक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमाओं, क्षेत्रों और पीढ़ियों के पार टीमवर्क की आवश्यकता है। भारत में भी खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिलता। इसकी वजह है खराब सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भंडारण की समस्या। लाखों टन अनाज खुले में सड़ जाता है, जबकि करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं। बच्चों में कुपोषण की समस्या भी गंभीर है। हमें इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है ताकि अनाज की बर्बादी रोकी जा सके और लोगों को उचित मात्रा में भोजन मिल सके।

भारत में शादी-विवाह जैसे समारोहों में बहुत सारा खाना बर्बाद होता है। एक शोध के अनुसार बेंगलुरु में शादियों में लगभग 950 टन खाना फेंका गया। समस्या सिर्फ खाने की बर्बादी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा कैलोरी वाला खाना भी एक समस्या है। भारत में कुपोषण की समस्या गंभीर है, जबकि अनाज की बर्बादी हो रही है। विश्व खाद्य उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार भारत में भुखमरी की समस्या से निपटने की गति धीमी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सभी लोगों के लिए पर्याप्त अनाज है, लेकिन फिर भी कई लोग भूखे हैं और कुपोषण से जूझ रहे हैं। हमें इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है। क्या सिर्फ कृषि उत्पाद बढ़ा कर और खाद्यान्न को बढ़ा कर हम भूख से अपनी लड़ाई को सही दिशा दे सकते हैं। चाहे विश्व के किसी कोने में इस सवाल का जवाब हाँ हो, लेकिन भारत में इस सवाल का जवाब ना है और इस ना की वजह है, खाद्यान्नों को रखने के लिए जगह की कमी। यूँ तो भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पिछले दशकों से बना हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों टन अनाज बर्बाद होता है।

चार अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय ने 12 अक्टूबर को सार्वजनिक किया। सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव शालिनी रजनिश को पत्र भेजकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इससे साफ हो गया कि कर्नाटक सरकार अब संघ के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अघोषित आपातकाल की तैयारी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष का उत्सव मना रहा है। समाज में संगठन के योगदान और उसके अनुशासन, सेवा व राष्ट्रभाव की भावना को लेकर देशभर में कार्यक्रम आरंभ हुए हैं। लेकिन अभी इस उत्सव की गूँज शुरू ही हुई कि कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। राज्य सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और मंदिरों में आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

प्रियांक खरगे की आपत्तिः वैचारिक या राजनीतिक –प्रियांक खरगे का आरोप है कि आरएसएस सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों में बिना अनुमति शाखाएं चला रहा है, जहां लाठी लेकर नारेबाजी की जाती है और बच्चों के दिमाग में नफरत भरी जाती है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि ये गतिविधियां संविधान की भावना और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हैं, इसलिए इन पर तत्काल रोक लगाई जाए। दरअसल ये पहली बार नहीं जब प्रियाँक ने ऐसा बयान दिया हो। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरे देश में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएगी। उस वक्त भी भाजपा ने इसे हिंदू-विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया था। अब वही विचार कर्नाटक में सरकारी दस्तावेज का रूप लेता दिख रहा है।

संघ पर प्रतिबंधों का इतिहासः हर बार और मजबूत होकर लौटा– इस संबंध में उल्लेखित है कि आरएसएस का इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रतिबंधों ने इसे कमजोर नहीं किया, यह ऐसे कठिन दौर में अत्यधिक संगठित रूप में ही लोगों के सामने आया है। आपको बतादें कि संघ पर पहला प्रतिबंध (1948)ः महात्मा गांधी की हत्या के बाद। नाथूराम गोडसे के कथित संबंध के नाम पर 4 फरवरी 1948 को बैन लगाया गया था, लेकिन 18 महीने बाद जांच में संघ निर्दोष पाया गया और 12 जुलाई 1949 को बैन हटा।

दूसरा प्रतिबंध (1975) में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में लगा। उस दौरान आरएसएस को अवैध घोषित किया गया, हजारों स्वयंसेवक जेल में ठूंस दिए गए, लेकिन इमरजेंसी खत्म होते ही संघ पहले से अधिक सक्रिय रूप में लौटा और जनसंघ-जनता पार्टी के पुनर्गठन में निर्णायक भूमिका निभाई। तीसरा प्रतिबंध (1992) में बाबरी विध्वंस के बाद पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने आरएसएस, विहिप और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया, जो 1993 में अदालत से हट गया क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

हर बार संघ ने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया। उसने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्रनिर्माण के कार्यों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चीन युद्ध से लेकर कोविड महामारी तक, हर संकट में संघ के स्वयंसेवक देश के आम जन की सेवा करते हुए और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाते हुए ही नजर आए हैं। वे राहत कार्यों में अग्रिम पंक्ति में रहते हैं। ऐसे में ये सवाल स्वभाविक तौर पर उठता है कि क्या कर्नाटक सरकार सचमुच संवैधानिक आधार पर कदम उठा रही है या फिर यह एक वैचारिक द्वेष से प्रेरित राजनीतिक रणनीति है

डिजिटल युद्धः #BanRSS अभियान और वैचारिक ध्रुवीकरण– सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से #BanRSS ट्रेंड कर रहा है। वामपंथी संगठनों, सेकुलर लॉबी और इस्लामी कट्टरपंथी समूहों से जुड़े कई हैंडल इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आरोप वही पुराने हैं; फासीवाद, संघी मानसिकता, हिंदू राष्ट्रवाद। दिलचस्प यह है कि इसी दौरान कुछ निष्क्रिय या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग भी इस मुहिम को हवा दे रहे हैं। जिस तरह यह ट्रेंड संगठित तरीके से फैलाया गया है, वह यह संकेत देता है कि यह केवल प्रियाँक खरगे का व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि एक सुविचारित वैचारिक मोर्चा है।

'शाखा' से डर क्यों– संघ की शाखाएं वर्षों से सार्वजनिक स्थानों पर लगती रही हैं; स्कूल के मैदान, पार्क या मंदिर परिसर, जहाँ न तो राजनीति होती है और न ही कोई प्रचार। वहां अनुशासन, योग, देशभक्ति और समाज सेवा की भावना सिखाई जाती है। फिर भी इन्हें निशाने पर लेना बताता है कि समस्या गतिविधियों से नहीं, विचार से है। संघ की विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ ही एकता और आत्मगौरव की भावना जगाती है। यही वह विचार है जो विभाजित राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता हुआ दिखाई देता है। कर्नाटक में कांग्रेसी सरकार का ये कदम बता रहा है कि कांग्रेस और वामपंथी तबके को संघ की सामाजिक पकड़ असहज करती है। जबकि संघ न तो चुनाव लड़ता है, न सत्ता की होड़ करता है। उसकी ताकत आम जन से सीधे संवाद और समाज सेवा से आती है, जो राजनीति से परे है।

कर्नाटक की राजनीतिः अंदरूनी कलह और ध्यान भटकाने की कोशिश

दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार इस समय कई मोर्चों पर घिरी है, बढ़ते महिला अपराध, बिजली संकट, पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार, और डी.के. शिवकुमार व सिद्धारमैया के बीच नेतृत्व संघर्ष जैसी चुनौतियाँ सामने हैं। ऐसे में आरएसएस पर बैन का मुद्दा सरकार के लिए ध्यान भटकाने का उपकरण बनता दिख रहा है।

विचारधारा बनाम राजनीति– यहां आरएसएस का प्रभाव इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, पिछड़े और महिलाओं को जोड़ने में उल्लेखनीय काम किया है। 'समरसता अभियान', 'सेवा भारती', 'विविध शिक्षण संस्थान' और 'वनवासी कल्याण आश्रम' जैसे संगठनों के जरिए संघ ने समाज के उस हिस्से तक पहुँच बनाई, जहाँ राजनीति कभी नहीं पहुँच सकी। यही कारण है कि संघ के विरुद्ध जब भी राजनीतिक बवंडर उठता है, वह वैचारिक रूप से कमज़ोर पड़ जाता है। संघ की शाखाएँ किसी पार्टी का मंच नहीं है, यह तो राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला हैं।

अघोषित आपातकाल की गंध– कर्नाटक में यदि सरकारी आदेशों के जरिए संघ की शाखाओं या गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश होती है, तो यह लोकतंत्र के मूलाधारों पर चोट होगी। संघ कोई अवैध संगठन नहीं, बल्कि भारत के संविधान के तहत एक सामाजिक संगठन है। ऐसे में प्रशासनिक दबाव डालकर उसकी गतिविधियां रोकना अघोषित आपातकाल जैसा कदम माना जाएगा। इसे 'सेकुलरिज्म' के नाम पर वैचारिक आतंक कहा जा सकता है; जहाँ असहमति को देशद्रोह और राष्ट्रवाद को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इतिहास यही कहता है कि जब भी संघ को दबाने की कोशिश हुई, जनता ने उसे और अपनाया। यह संगठन सत्ता या विरोध से नहीं, समाज की स्वीकृति से जीवित है। कर्नाटक में यदि कांग्रेस यह मानती है कि वैचारिक दमन से संघ को कमजोर किया जा सकता है, तो यह वही भूल दोहराना होगा जो 1948, 1975 और 1992 में की जा चुकी है। यदि किसी लोकतांत्रिक राज्य में समाज सेवा करने वाले संगठन को 'खतरा' मान लिया जाए, तो यह लोकतंत्र की पराजय होगी, न कि उसकी सुरक्षा। संघ का सौ साल का इतिहास भी यही गवाही देता है कि जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आत्मा से जुड़ा है, उसे कोई राजनीतिक तूफान मिटा नहीं सकता है।

दशहरा और दिवाली के बीच के ये बीस दिन : एकात्मता और समरसता का काल

भारतीय संस्कृति में हर पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि गहन सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देने वाला माध्यम है। विजयादशमी और दीपावली के बीच आने वाले बीस दिन इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ये केवल कैलेंडर की बीस तिथियां नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, समरसता और सहयोग की भावना जगाने की अवधि हैं। यह वही काल है जब श्रीराम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे। रामजी की इस वापसी यात्रा और दीपावली की तैयारी के बीच गहरा सांस्कृतिक और मानवीय संबंध है।

रमेश शर्मा

रावण-वध के बाद का काल, एकात्मता की यात्रा- रामचरितमानस के अनुसार रावण-वध अश्विन शुक्ल दशमी को हुआ था, जिसे हम आज विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। किंतु श्रीराम अयोध्या लौटे कार्तिक अमावस्या को, अर्थात् बीस दिन बाद। यह विलंब उत्सव या विश्राम का नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण का था। रामजी लंका-विजय के पश्चात केवल दो दिन वहीं ठहरे, एक दिन रावण और उसके परिजनों के अंतिम संस्कार हेतु, और अगले दिन विभीषण के राज्याभिषेक के लिए। इसके बाद उन्होंने विभीषण से अनुमति लेकर पुष्पक विमान से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। परंतु वे सीधे अयोध्या नहीं लौटे। उन्होंने उसी मार्ग से यात्रा की, जिससे वे वनवास में और लंका युद्ध के लिए गए थे।

रामजी हर आश्रम, हर ग्राम, हर वन्य समाज से पुनः मिले। ऋषियों, तपस्वियों, वनवासियों, भील, निषाद, किरात सभी से संवाद किया। यह यात्रा केवल वापसी नहीं थी; यह पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बाँधने की प्रतीक थी। उन्होंने हर समाज-समूह को साथ चलने का निमंत्रण दिया, और अनेक समाज प्रमुख पुष्पक विमान में उनके साथ चले। इन अठारह दिनों में रामजी ने समाज को यह संदेश दिया कि यदि समाज संगठित रहेगा, तो कोई भी आसुरी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती।

रामजी का संदेश; आभार और एकता– रामजी ने इस यात्रा के माध्यम से यह भी बताया कि जो लोग कठिन समय में साथ देते हैं, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। निषादराज, सुग्रीव, विभीषण, शबरी, जटायु जैसे सहयोगियों के प्रति उनका सम्मान इसका प्रमाण है। उन्होंने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि जाति, वर्ग, वर्ण या स्थिति कोई भी हो, सहयोग और सद्भाव ही सच्चा धर्म है।

दीपावली की तैयारी, समाज की एकता का उत्सव– रामजी के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यही परंपरा आगे चलकर दीपावली के रूप में विकसित हुई। परंतु दीपावली केवल दीप प्रज्ज्वलन का त्यौहार नहीं है, यह समाज के हर वर्ग की सहभागिता का उत्सव है। दीपावली की तैयारी दशहरे के तुरंत बाद प्रारंभ होती है। घरों की सफाई, लिपाई-पुताई, नई वस्तुओं की खरीदारी, घरों और बाजारों की सजावट, इन सबमें समाज के हर वर्ग का श्रम और योगदान होता है। कोई झाड़ू बनाता है, कोई रंग, दीये, मिठाइयाँ या आभूषण। कोई घर सजाता है, तो कोई वस्तुएँ बेचता है। यह सामूहिक श्रम और परस्पर सहयोग ही दीपावली की आत्मा है।

यही कारण है कि दीपावली के दिन केवल लक्ष्मी पूजन नहीं होता, बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के परिश्रम और सहभागिता का सम्मान है। यह पर्व बताता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पेशे, वर्ग या स्थान से जुड़ा हो, समाज की समृद्धि में समान रूप से भागीदार है।

भारतीय संस्कृति की समरस दृष्टि– भारतीय परंपरा में वसुधैव कुटुम्बकम् केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन-मूल्य है। यहाँ हर प्राणी को समान सम्मान देने की भावना है। रामायण इसका सजीव उदाहरण है; रामजी के मित्र सुग्रीव, निषादराज, विभीषण और हनुमान भिन्न समाजों से थे, परंतु सब समान सम्मान के पात्र थे। भारतीय संस्कृति ने कभी जन्म, वर्ग या वर्ण के आधार पर श्रेष्ठता नहीं मानी। यहाँ कर्म और गुण ही पहचान हैं। इसलिए चाहे वनवासी हों या नगरवासी, किसान हों या व्यापारी, सब एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएँ अलग-अलग दिशाओं में फैलती हैं, पर मूल एक ही होता है, उसी प्रकार विविध समाज और समुदाय मिलकर एक ही मानवता का वृक्ष बनाते हैं।

दीपोत्सव ः केवल रोशनी नहीं, सामाजिक नवजीवन– दीपावली के दिनों में केवल घर नहीं, पूरा समाज आलोकित होता है। यह बाहरी स्वच्छता के साथ भीतरी शुद्धता का प्रतीक है। पुरानी वस्तुओं को हटाना, नई चीज़ों को लाना, यह केवल भौतिक क्रिया नहीं बल्कि नवजीवन का संकेत है। दीपावली के माध्यम से समाज में श्रम का सम्मान, सहयोग की भावना और सामूहिक प्रगति का आदर्श स्थापित होता है। यह केवल धन या सौभाग्य का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मबल, विश्वास और परस्पर जुड़ाव का पर्व है।

रामायण का सन्देश और आज का समाज– युग बदल गए, परंतु रामायण का यह सन्देश आज भी प्रासंगिक है। विजयादशमी से दीपावली तक का यह काल हमें याद दिलाता है कि समाज का सच्चा बल संगठन, प्रेम और परस्पर सहयोग में है। यदि समाज विभाजित होगा, तो दानवी शक्तियाँ प्रबल होंगी; यदि संगठित रहेगा, तो सुसंस्कृत जीवन सुरक्षित रहेगा। आज भी जब हम दीप जलाते हैं, तो केवल श्रीराम की अयोध्या वापसी नहीं, बल्कि उसी एकता और समरसता की ज्योति जलाते हैं जो भारत की आत्मा है। दीपावली का यह प्रकाश हमें याद दिलाता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कारीगर हो, किसान हो, व्यापारी हो या गृहिणी राष्ट्र के इस दीपोत्सव का समान सहभागी है।

अतः विजयादशमी से दीपावली तक के बीस दिन केवल धार्मिक या पौराणिक महत्व के नहीं हैं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से यह आत्मसात करने का काल है। यही अवधि हमें सिखाती है कि उत्सव का अर्थ केवल आनंद नहीं, बल्कि परिश्रम, सहयोग और समरसता है। रामजी ने लंका विजय के बाद जिस एकात्मता का संदेश दिया, वही आज दीपावली की तैयारी में झलकता है; सब एक-दूसरे के पूरक हैं, सबकी आवश्यकता है, और सबका सम्मान समान है। यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, यही राष्ट्र की शक्ति है। इस प्रकार दशहरा और दीपावली के बीच के ये बीस दिन केवल दो पर्वों के बीच का अंतराल नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और समाज को एक सूत्र में बाँधने की जीवंत अवधि हैं, जो हमें यह सिखाती है कि जब सब एक-दूसरे के दीप बन जाएँ, तभी सच्ची दीपावली होती है।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह 1 नवम्बर को मनाया जायेगा

कलेक्टर ने ली समय-सीमा प्रकरणों की बैठक

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य के 70वां स्थापना दिवस समारोह मैहर में एक नवम्बर को अलाउद्दीन खां स्टेडियम में प्रात: 10.25 बजे से मनाया जायेगा। इस अवसर पर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, संदेश वाचन की गतिविधियों के अलावा कार्यक्रम स्थल पर विकास को रेखांकित करती हुई आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी। कलेक्टर मैहर रानी बाटड ने बुधवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में स्थापना दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम को गरिमामय तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर संजना जैन, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम अमरपाटन डॉ. आरती सिंह, रामनगर एसपी मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. एलके तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव,

डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, जिला संयोजक डॉ. अरूण शुक्ला, आरटीओ संजय श्रीवास्ताव, जनपद सीईओ एमएल प्रजापति, वेदमणि मिश्रा, अशोक तिवारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर रानी बाटड ने कहा कि मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सार्वजनिक महत्व की ऐतिहासिक इमारतों एवं शासकीय भवनों पर रात्रि में रोशनी की जायेगी। स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम पूर्ण गरिमा के साथ संपन्न कराये जाये। इस अवसर पर स्व-सहायता समूह के उत्पादों के साथ प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी। प्रदर्शनी के प्रभारी सीईओ जनपद पंचायत मैहर होंगे। कलेक्टर ने अन्य विभागों के अधिकारियों को भी स्थापना दिवस के आयोजन की जिम्मेदारियां सौंपी। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी विभागों की 50 दिवस और 100 दिवस से ऊपर की शिकायतों की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके विभाग की 100 दिवस से ऊपर की कोई भी शिकायत तथा जनवरी 2024 के पहले की कोई शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। कलेक्टर ने नाट-अटेण्ड रही शिकायतों की जानकारी लेते हुए कहा कि किसी भी विभाग में नाट-अटेण्ड शिकायतें मिली तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मत्स्य और मछुआ कल्याण विभाग की कुल 3 शिकायतों में से 2 शिकायतों के नाट-अटेण्ड मिलने पर सहायक संचालक मत्स्य अंजना सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर-कमिश्नर कान्फ्रेंस के निर्णयों की जानकारी देते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों को भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नामांकन शिक्षा की गुणवत्ता एवं अन्य विभागों में मैहर जिले की स्थिति कमजोर रही है। उसमें सुधार लाये। जनजाति विभाग के आवासीय आश्रम छात्रावासों में सीट रिक्त रहने पर जिला संयोजक के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में भरपूर राशि होने के बावजूद भी निरीक्षण के दौरान सुविधाओं की कमी दिखती है। कलेक्टर ने कहा कि स्कूल, आंगनवाडी केन्द्र और छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण करें और निरीक्षण रिपोर्ट परख ऐप पर भी अपलोड करना जरूरी है।

शिक्षा विभाग के समन्वय से आदिवासी छात्रावासों की सीटें फुल करायें : शैलेन्द्र सिंह

सीईओ जिला पंचायत ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने मैहर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला शिक्षा केन्द्र, शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर विभागीय गतिविधियां की समीक्षा की। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव, डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, जिला संयोजक डॉ. अरूण शुक्ला, सीईओ जनपद एमएल प्रजापति, वेदमणि मिश्रा, अशोक तिवारी, सभी बीईओ, बीआरसीसी भी उपस्थित रहे।

सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में सीटें रिक्त रह गई है। उन्हें शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों से समन्वय कर पूर्ति कराये। डीपीसी ने बताया कि जिला शिक्षा केन्द्र के सभी छात्रावासों में प्रवेशित छात्रों की सीटों के अनुसार शत-प्रतिशत पूर्ति कर ली गई है। मैपिंग के अनुसार कक्षा 1 में पिछले वर्ष की तुलना में 119 प्रतिशत प्रवेशित छात्रों की वृद्धि हुई है। सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों और यूनिफार्म का वितरण कर दिया गया है। जिले को प्राप्त साइकिलों का वितरण भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के रूप में मैहर जिले के 941 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसी प्रकार एफएलएन कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 4 तक की प्रत्येक ब्लाक में 10-10 शालायें शामिल की गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ई-अटेंडेंस में सुधार की आवश्यकता है। मैहर ब्लाक में सबसे कम 37 प्रतिशत रामनगर में 50 प्रतिशत तथा अमरपाटन में 60 प्रतिशत ई-अटेंडेंस ली जा रही है। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक और गेस्ट फैकलिटी का ई-अटेडेंस का प्रतिशत बेहतर है। जिला स्तर से टीम बनाकर प्रतिदिन 8 से 10 स्कूलों की मानीटरिंग की जा रही है। मैहर जिले में पात्र 2803 विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि और वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में फर्स्ट रैंक के छात्रों को स्कूटी प्रदान की गई है। जिले में स्वच्छ हरित विद्यालयों के रूप में 750 विद्यालयों का चयन किया गया है।

राष्ट्र रिषी नाना जी देशमुख के सारथी थे संजय

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। संजय विश्वकर्मा (संजू), निवासी पिड़रा की सारथी बनने की यात्रा 1995 की है, जब संघ का शिविर बरौधाके पास लगा था। समापन समारोह में राष्ट्र रिषी नाना जी देशमुख पहुंचे थे। उनसे प्रभावित होकर संजय ने उनकी सेवा करने का मन बना लिया और चित्रकूट स्थित सियाराम कुटी में पहुंच गए।

कुछ दिनों तक सेवा करने के बाद उन्हें नाना जी का वाहन चालक बना दिया गया। जब तक नाना जी का शरीर रहा, तब तक संजय ने पूरे भरोसे के साथ उनकी सेवा की। नाना जी उन पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन जब नाना जी का शरीर शांत हो गया, तो दो-तीन साल बाद उनके प्रति कुचक्र रखा गया। तत्कालीन अधिकारियों ने

कुछ शर्तें रखीं, जिनका पालन संजय ने नहीं किया, जिसके कारण उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया। संजय विश्वकर्मा और संजू यही बताना चाहते हैं कि शासन चाहे किसी का हो, लेकिन दुशासन हमेशा रहते हैं। प्रयोजन चाहे कुछ भी हो, पर संजय के मुताबिक चित्रकूट विकास प्राधिकरण की मनमानी चरम पर है। ऐसे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो नियमों की अवहेलना कर सरकारी पैसे को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं।

आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना, कंजर्वेशन रिजर्व का विरोध; मझगवां-परसमनिया में है प्रस्तावित

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले में बुधवार को ग्रामीण और आदिवासी समुदायों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक दिवसीय आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने परसमनिया पठार और मझगवां क्षेत्र को वन विभाग द्वारा रिजर्व कंजर्वेशन में शामिल किए जाने का विरोध किया। उन्होंने एसडीएम सिटी को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों की मुख्य मांग है कि परसमनिया पठार और मझगवां क्षेत्र को रिजर्व कंजर्वेशन से मुक्त रखा जाए। उनका तर्क है कि ऐसा न होने पर वहां के ग्रामीणों और किसानों की आजीविका पर संकट आ जाएगा।

कंजर्वेशन रिजर्व का कर रहे विरोध: इसके अतिरिक्त, उन्होंने वन भूमि पर वर्षों से काबिज आदिवासी परिवारों का सत्यापन कर उन्हें मालिकाना हक दिलाने और वैध पट्टे जारी करने की मांग की। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जिन भूमियों पर आदिवासियों के नाम पट्टे दर्ज हैं, लेकिन उन पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है, उन्हें वास्तविक लाभार्थियों को वापस दिलाया जाए।

एससी-एसटी एक्ट का सख्ती से पालन कराने की मांग

आदिवासियों ने यह भी शिकायत की कि अन्याय या जातिसूचक अपमान की घटनाओं पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, इसलिए एससी-एसटी एक्ट का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में निवासरत कोल जनजाति परिवारों का सर्वे कर उन्हें धारणा अधिकार के तहत पट्टे प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। आंदोलन के दौरान, एसडीएम राहुल सिलड़िया और सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने ग्रामीणों को समझाइश दी।

बरौंधा बस स्टैण्ड से लगी करोड़ों की मध्यप्रदेश शासन की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाए प्रशासन : आशुतोष

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और चित्रकूट विधानसभा के कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने प्रेस में जारी किए गए बयान में कहा कि इन दिनों बरौंधा में मध्य प्रदेश शासन की जमीनों पर रसूखदारों की नजरें गड़ी हुई हैं। बरौंधा बस स्टैंड से लगे रखवा नंबर 257, 472, 266, 258 में सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जा कर घर और दुकान बना रखी हैं। आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि लोग पहले मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर कच्चा निर्माण कर कब्जा करते हैं और फिर उस भूमि को महंगे दामों में बेचकर मोटी रकम वसूलते हैं। कुछ नंबरों के अंश भागों पर अगर पट्टा 500 वर्गफुट का है, तो कब्जा 5000 वर्गफुट में करके बड़ी-बड़ी गोदामें और ट्रेडर्स का कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि सन 58 और 59 के रिकॉर्ड देखे जाएं, तो लोगों के पूर्वज अपने रसूखों के चलते फर्जी पट्टे भी बनवाए हुए हैं। यदि इस मामले की जांच की जाए, तो मध्य प्रदेश शासन की करोड़ों की भूमि अतिक्रमण मुक्त हो सकती है। इस भूमि का उपयोग बच्चों के लिए खेल के मैदान, विद्यालय का निर्माण और अस्पताल के निर्माण के लिए किया जा सकता है। आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि पटवारी आवास, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, थाना परिसर और अस्पताल की भूमि के कुछ भागों में भी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि समस्त शासकीय कार्यालयों और समस्त आवंटित शासकीय मध्य प्रदेश शासन की भूमियों का सीमांकन करवाकर अतिक्रमण कार्यों को चिन्हित किया जाए और अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाए। आगे द्विवेदी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मध्य प्रदेश शासन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया जाता, तो मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट की शरण में जाकर जनहित याचिका के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

कन्या भोज से प्रारंभ हुआ 44 वां वरसी महोत्सव

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सदगुरु बाबा मनोहर शाह साहब जी का 44 वां वरसी महोत्सव कंवर नगर सिन्धी कॉलोनी स्थित श्री मनोहर धाम में महंत स्वामी संतोखदास उदासीन जी के सानिध्य में 15 अक्टूबर बुधवार को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ हुआ। आश्रम के सेवादारी राजू रामानी और प्रकाश चांदवानी ने बताया कि वरसी महोत्सव का भव्य शुभारंभ 15 अक्टूबर को प्रात: 10:30 बजे सत्संग से हुआ। इसके बाद दोपहर 12:00 बजे आरती एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कन्याओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।

कन्या भोज ने इस महोत्सव में विशेष रंग भर दिया और सभी उपस्थित लोगों ने इस अवसर का आनंद लिया।

सत्संग संध्या में सायं 7:30 बजे माता की चौकी एवं सुंदर सांस्कृतिक झांकी व नृत्य का आयोजन किया गया, जिसे बाहर से आए हुए कलाकारों ने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया और उपस्थित दर्शकों ने कलाकारों की सराहना की।

16 अक्टूबर गुरुवार को प्रात: 9:30 बजे सत्संग का आयोजन होगा, इसके बाद सुबह 10:30 बजे हवन यज्ञ का कार्यक्रम होगा। 12:30 बजे संत महात्माओं का शुभ आगमन होगा और हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद संत महात्माओं और ब्राह्मण समाज का भोजन होगा। शाम 6:00 बजे महंत स्वामी संतोखदास जी द्वारा सत्संग का आयोजन किया जाएगा, और रात्रि 8:00 बजे से कटनी से पधारे श्री गोवर्धन दिलीप बालक मंडली द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित 5-वां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। नगर पालिक निगम सतना को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में फास्टेस्ट मूवर (50 हजार से 3 लाख की श्रेणी) में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने पर माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन और प्रतिमा बागरी, राज्यमंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सम्मानित किया गया।

यह समारोह नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न नगर निगमों और पालिकाओं को उनकी स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। नगर पालिक निगम सतना की ओर से यह पुरस्कार राजेश चतुर्वेदी, अध्यक्ष नगर पालिक निगम सतना, एमआईसी सदस्य गोपी गेलानी, आदित्य यादव, डॉ. शेर सिंह मीना (आयुक्त नगर पालिक निगम सतना), सिद्धार्थ सिंह, अरविन्द प्रताप सिंह और रोजल प्रताप सिंह ने प्राप्त किया।

इस अवसर पर माननीय महापौर योगेश ताम्रकार ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार जनता का पुरस्कार है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा एक आयोजन नहीं बल्कि एक आंदोलन है। हमें इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि अगले वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक रूप से और बेहतर स्थान प्राप्त कर सकें। महापौर ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता के इस आंदोलन में भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नगर निगम की टीम की मेहनत और जनता के सहयोग का परिणाम है।

तम्बाकू मुक्त युवा अभियान की बैठक संपन्न

मैहर। कलेक्टर मैहर रानी बाटड की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न तम्बाकू मुक्त युवा अभियान की जिला स्तरीय बैठक में बताया गया कि 9 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक जिले में अभियान स्वरूप विभिन्न गतिविधियां संचालित की जायेगी। इनमें इस अवधि में कम से कम 20 ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने की कार्यवाही तथा लगभग 50 स्कूल परिसरों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित करने के संबंध में प्रयास किये जायेंगे। इसके अलावा सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों के परिसरों में तम्बाकू का सेवन करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 200 रूपये की पेनाल्टी लगाई जायेगी।

सम्मानित किए गए डायरेक्टर आनंद

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। विगत दिनों सतना शहर स्थित टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अमरपाटन स्थित तक्षशिला एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक आनंद द्विवेदी को सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार, एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाह और न्यूज चैनल के अधिकारियों द्वारा उन्हें शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान आनंद द्विवेदी के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया है।

तक्षशिला एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर श्री द्विवेदी को इसके पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र

में कई प्रकार के नवाचार किए हैं, जो छात्रों के विकास में सहायक साबित हो रहे हैं। द्विवेदी का मानना है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा और संस्कारी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उन्होंने समाज को सही दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस सम्मान से न केवल आनंद द्विवेदी को प्रेरणा मिली है, बल्कि यह अन्य शिक्षकों और संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा में कार्य किया जाए, तो उसे सराहा जाएगा।

राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुए मनोज

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गो आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें गहन चिंतन किया गया। सम्मेलन का आयोजन खुशी सेंटर ने किया था। इस सम्मेलन में पंचगव्य से पंच परिवर्तन विषय पर अपने विचार रखते हुए देश भर से आए विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के उपरांत दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें गो आधारित नीतियों और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगामी कार्य योजना प्रस्तुत की गई।

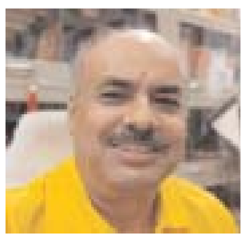

मिशन भारत के सीईओ साकेत मणि त्रिवेदी ने वर्ष 2047 तक गाय आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से 35 ट्रिलियन डॉलर की दृष्टि पर अपने विचार रखे। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काऊ बेस्ड इंडस्ट्रीज के संस्थापक डॉ. वल्लभभाई कथीरिया ने विश्वभर के गो उद्यमियों और गौ प्रेमियों के संगठित प्रयासों और सहयोग पर बल देते हुए कहा कि गाय ही स्वस्थ, समृद्ध और उज्ज्वल विश्व की आधारशिला है।

इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एस.पी. बघेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, तथा अनेक विशिष्ट अतिथियों ने अपनी प्रत्यक्ष और परोक्ष उपस्थिति एवं शुभकामनाएं दर्ज कराई। मध्य प्रदेश से इस सम्मेलन में दिलीप धनराज, मनोज प्रताप सिंह, भागीरथ तिवारी, गंभीर सिंह राजपूत, मीनाक्षी शर्मा, पूरी शर्मा आदि उपस्थित रहे।

मादक पदार्थों का रोकने सभी विभाग अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करें : रानी बाटड

जिला स्तरीय नार्कोटिक्स समन्वय समिति की बैठक संपन्न

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नार्कोटिक्स क्वार्डिनेशन की जिला स्तरीय समिति की संपन्न बैठक में नशीले पदार्थो के उपयोग को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम डॉ. आरती सिंह, एसपी मिश्रा, आरटीओ संजय श्रीवास्तव, सीएमएचओ डॉ. एलके तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र बांगरे, आरआई नृपेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।

कलेक्टर रानी बाटड ने कहा कि नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने और मादक पदार्थो के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने सभी विभाग अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करें। लोगों में जागरूकता लाने अवारनेंस कैंप भी लगायें। उन्होंने जनपद सीईओ को कहा कि अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रतिमाह कम से कम एक कार्यक्रम नशा मुक्ति का आवश्यक रूप से करवाये। कार्यक्रम में स्थानीय एनजीओ एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी ले। कलेक्टर ने कहा कि समिति की हर तीन माह में बैठक होगी और इसमें समन्वय के साथ की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि नार्कोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाईयों के रोकथाम के तहत 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 25 प्रकरणों में 35 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। इनमें 17 किलो 851 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 1 लाख 88 हजार रूपये और नशीली कफ सिरप कोरेक्स की 2843 शीशियां कीमत 5 लाख 43 हजार 525 रूपये की जप्ती की गई है। इसके अलावा जुलाई माह में मैहर पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी अभियान के दौरान 7 थानों में 155 कार्यक्रम किये जाकर 25 हजार 790 आम नागरिकों, छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मादक पदार्थो के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति आमजन को जागरूक करने पंचायत, ब्लाकवार जागरूकता कैम्प आयोजित किये जाये।

सीएमएचओ ने किया मैहर के मेडीकल स्टोरों का निरीक्षण

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। कलेक्टर मैहर रानी बाटड के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी और डॉ. प्रदीप गौतम ने मैहर शहर की दवाई की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने प्रतिबंधित कप सिरप एवं अन्य प्रतिबंधित दवाओं की उपलब्धता की जांच की गई। संबंधित मेडीकल स्टोरों में प्रतिबंधित कप सिरप का स्टाक नहीं पाया गया।

रतलाम में 8 लेन पर खड़े ट्रक में घुसी पिकअप

रतलाम, एजेंसी। रतलाम से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह लहसुन से भरे खड़े आयशर ट्रक में पिकअप पीछे से जा घुसी। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर मौत हो गई। क्लीनर भी गंभीर घायल हो गया है। हादसा रावटी थाना अंतर्गत माही नदी के पास हुआ है। पिकअप वाहन मुर्गे से भरा हुआ था। झाबुआ से लेकर रतलाम आ रहे थे। सुबह करीब 8.30 बजे पिकअप खड़े आयशर में जा घुसी। हादसा इतना खतरनाक था कि पिकअप का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में पिकअप चालक अनवर हुसैन (44) पिता लियाकत निवासी कैलाश मार्ग झाबुआ की मौके पर मौत हो गई। क्लीनर फिरोज मंसूरी (41) पिता फकीर मोहम्मद निवासी झाबुआ गंभीर घायल हो गया। मृतक का शव पीएम के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया। घायल को भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया है। रावटी थाना प्रभारी दीपक मंडलोई ने बताया कि खड़े आयशर ट्रक में पिकअप पीछे से जा घुसा है। झाबुआ की तरफ से रतलाम आ रहे थे। उस दौरान हादसा हुआ है,। घटना की जांच की जा रही है।

किसान के घर से 2 लाख की चोरी :घर में सो रहा था परिवार चोरों ने चुराए 2 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर

नर्मदापुरम, एजेंसी। जिले के केसला थाना क्षेत्र में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक किसान के घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर दरवाजे की कुंडी खोलकर घर के अंदर घुसे और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। चोरी के दौरान घर में किसान और उसका परिवार मौजूद था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब परिजन उठे, तब वारदात का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक, फरियादी नर्मदाप्रसाद यादव निवासी ताकू रोड अहीरपुरा केसला किसान हैं। उन्होंने बताया कि बीती रात वे अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि कमरे का सामान बिखरा हुआ था और अलमारी खुली हुई थी। जब अलमारी की जांच की गई, तो सोने-चांदी के जेवर गायब मिले। चोरी की जानकारी मिलते ही केसला थाना प्रभारी उमाशंकर यादव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार, चोरों ने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोलकर घर में प्रवेश किया और बिना किसी शोर-शराबे के चोरी को अंजाम दिया। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब दो लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आसपास के संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों का सुराग मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस टीम अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इस वारदात के बाद इलाके में लोगों में डर और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने भी रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

गोवंश तस्करी के आरोपी गिरफ्तार : टेम्पो से दो गौवंश छुड़ाए, वाहन जब्त

खरगोन, एजेंसी। जिले में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर पुलिस ने मंगलवार को गोवंश तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। खलटाका पुलिस चौकी के चेकिंग पॉइंट पर की गई इस कार्रवाई में एक टेम्पो से दो गौवंश मुक्त कराए गए, जिन्हें क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर खलघाट की ओर से आ रहे एक सफेद सुपर कैरी टेम्पो (स्क्व46श्व1518) को घेराबंदी कर रोका गया। वाहन में ले जाए जा रहे गोवंश के संबंध में आरोपियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान करण पिता विनायक भाबर और वाहन मालिक सागर पिता मोहन शिंदे के रूप में हुई। दोनों सेंधवा के दावलबैडी निवासी हैं। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इंदौर हाईवे पर किसानों का चक्काजाम

औने-पौने दाम पर मक्का उपज खरीदने का आरोप, रोड़ पर अड़ाएं ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 घंटे बाद जाम खुला

खंडवा, एजेंसी। किसानों का गुस्सा उस वक्त फूट गया, जब मंडी में उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिला। किसानों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर मंडी के बाहर इंदौर हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। जिससे दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रुक गई और लंबा जाम लग गया। किसानों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बात की। 3 घंटे चक्काजाम के बाद किसानों और प्रशासन के बीच एक राय बनी।

मक्का की फसल के दाम बढ़ाने की मांग

किसानों का कहना है कि, मक्का की उपज लेकर वे लोग मंडी पहुंचे तो सुबह 10 बजे की नीलामी में मक्का उपज की बोली 700 रूपए क्विंटल से शुरू की गई। किसान पर इतना भी अत्याचार क्या होता है कि वो पहले ही मरा है, और मंडी आए तो यहां व्यापारी मार दे रहा है।

किसानों का आरोप केवल खंडवा मंडी में दिक्कत बाकी जगह सही दाम

ये कोई भाव है क्या, विरोध करते हैं तो कहते हैं उपज में नमी है, अब बताओ कि क्या हम लोग उपज को पानी में भिगोकर ला रहे क्या? ये हाल सिर्फ खंडवा कृषि उपज मंडी के हैं। बाकी जगह तो फिर भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। खंडवा मंडी वाले चोर हैं, जो व्यापारियों के साथ मिलकर किसानों को लूट रहे हैं।

11 बजे से 1 बजे तक जाम लगा रहा

किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते इंदौर नाका पर दो घंटे तक चक्काजाम लगा रहा। सुबह 11 बजे शुरू हुआ आंदोलन दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों ने सिर्फ एंबुलेंस को रास्ता दिया, बाकी सभी वाहन रुके रहे। यहां से कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, इसलिए इंदौर-खंडवा मार्ग पर बसों का संचालन बंद हो गया। इंदौर से आने वाली बसों ने यात्रियों को किशोर कुमार समाधि स्थल के पास ही उतार दिया। यात्रियों को आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को लेने जा रहे माता-पिता भी जाम में फंसे रहे, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। प्रशासन ने बातचीत के बाद जाम खुलवाया।

अफसरों ने किसानों से और व्यापारियों से बात की

जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर और सीएसपी अभिनव बारंगे मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद एसडीएम ऋषि सिंघई और अपर कलेक्टर अरविंद चौहान भी पहुंचे। डीडीए नितेश यादव ने किसानों से बातचीत की और कहा कि उनकी सभी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसान लिखित आश्वासन मांगते रहे।

अधिकारियों ने मौके पर व्यापारियों को भी बुलाया और बातचीत की। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में सैकड़ों लाइसेंसधारी व्यापारी हैं, लेकिन नीलामी के समय सिर्फ 2-3 व्यापारी ही आते हैं।

वही अपनी मोनोपॉली (एकाधिकार) चलाते हैं और मनमाने भाव तय करते हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। वहीं डीडीए यादव के मुताबिक, मंडी सचिव ओपी खेड़े बीमार हैं, वे इंदौर में भर्ती हैं।

किसानों ने रखी ये मांग

1. मक्का की कीमत तय करो
किसानों ने कहा कि सरकार ने मक्का की एमएसपी 2200 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। फिर भी व्यापारी 700 रुपये प्रति क्विंटल में खरीद रहे हैं। अगर उपज में नमी है, तो भाव उसी के अनुसार तय होना चाहिए। पर व्यापारी मनमानी कर रहे हैं।

2. परिवहन भाड़ा मिले या मंडी में खाली कराओ
किसानों ने बताया कि उपज की नीलामी के बाद उन्हें खुद वाहन से व्यापारी के गोदाम तक जाना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है। किसानों की मांग है कि उपज मंडी में ही खाली कराई जाए, या फिर उन्हें भाड़े का भुगतान मिले।

3. सभी तौल कांटे चालू करो
मंडी में फिलहाल सिर्फ एक तौल कांटा चल रहा है। सुबह नीलामी के बाद शाम 6-7 बजे तक तौल का काम चलता है। किसानों ने कहा कि मंडी के पास तीन कांटे हैं, तो सभी को चालू किया जाए। इससे समय बचेगा और परेशानी कम होगी।

4. भुगतान तुरंत दो
किसानों की मांग है कि उपज का भुगतान उसी समय मंडी में ही किया जाए। अभी व्यापारी रात 2 बजे तक पेमेंट करते हैं। मंगलवार को एक किसान को रात 12 बजे भुगतान मिला। घर जाते समय उसका एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। किसान बोले, भुगतान में देरी जानलेवा साबित हो रही है।

5. अवैध वसूली बंद करो
किसानों ने बताया कि मंडी में अवैध वसूली हो रही है।

सागर में शादी के तुरंत बाद गहने-नकद लेकर दुल्हन फरार-भाई को पुलिस ने पकड़ लिया

सागर, एजेंसी। कैंट थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। रिश्तेदार के माध्यम से बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे की शादी कराई। बहू घर आई, लेकिन रात में ही गहने और नकद रुपए लेकर भाग गई। मामले में पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

कैंट थाने के सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने शिकायती आवेदन में बताया कि उनके बेटे की शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे। इसी बीच मेरे रिश्तेदार राजू यादव निवासी मेढ़की ने एक रिश्ता बताया। 31 अगस्त को मेरे घर राजू अपने साथ उक्त लड़की को लेकर आया। जिसका नाम आरती यादव होना बताया गया। उसके साथ लड़की का कथित भाई रामनाथ भी था। घर पर लड़का और लड़की ने एक-दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ता पक्का होने पर राजू ने कहा कि लड़की पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।

कहकर पति को थाने के पास ले गई था, वहीं से भागी

दोनों पक्षों की शादी का खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। उसी समय ओली फलदान का कार्यक्रम किया गया। जिसमें मैंने 31 हजार रुपए और चांदी के पायल आरती को दी। इसके बाद 12 सितंबर को मेरे घर पर मेरे लड़के और आरती की शादी हिन्दू रीति रिवाज से कराई। लड़का-लड़की ने एक-दूसरे को माला पहनाकर शादी की रस्म पूरी की। उस समय घर पर आरती का भाई रामनाथ और राजू भी मौजूद थे। इस दौरान आरती को नेग के रूप में 50 हजार रुपए नकद, सोने का हार, चांदी की करधौनी, एक सोने के पैंडल का मंगलसूत्र दिया।

बाइक पर बैठकर घर जाने का बोला, मगर आई नहीं

शिकायत में महिला ने बताया कि बेटे ने मुझे बताया कि 14 सितंबर की रात करीब 11.30 बजे आरती ने कहा कि मेरे भाई रामनाथ का मुझे फोन आया है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। जिस पर हम दोनों उनसे मिलने के लिए कैंट थाने पैदल गए थे। थाने के बाहर थोड़ी दूरी पर रामनाथ बाइक लेकर खड़ा था। वहां से तीनों थोड़ी दूर गए। जहां आरती बोली कि मैं बाइक से घर तल चली जाती हूं। तुम पैदल आ जाओ। जब बेटा घर आया तो आरती और उसका भाई नहीं मिले। संदेह होने पर घर में देखा तो आरती को दिए 81 हजार रुपए नकद, सोने का हार, करधौनी, मंगलसूत्र, पायल नहीं थे। इसी दौरान बेटे ने बताया कि आरती मेरे साथ पति-पत्नी जैसे संबंध नहीं बनने दे रही थी। वह मुझसे दूर भाग रही थी। मेरे और बेटे के साथ शादी के नाम पर ठगी की गई है। शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को मामला जांच में लिया है। कैंट थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि शिकायत पर जांच करते हुए मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

4 माह की गर्भवती महिला ने लगाई फांसी

छतरपुर में मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया

छतरपुर, एजेंसी। महाराजपुर थाना क्षेत्र के बिकौरा गांव में मंगलवार रात एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला चार माह की गर्भवती थी। उसकी शादी छह माह पहले हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना व हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतका की पहचान डिगौनी गांव की रहने वाली 20 साल की जयंती पटेल के रूप में हुई है। छह माह पहले ही उसकी शादी चौड़ा खेड़ा धाम में बिकौरा गांव के रहने वाले धर्मेंद्र पटेल के साथ हुई थी। धर्मेंद्र चंदला अस्पताल में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है।

परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया: मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग मायके की जमीन बेचने और पैसों की मांग कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जयंती की हत्या कर उसे फंदे पर लटकाया गया है, क्योंकि उसके शरीर और पैरों पर चोट के निशान हैं।

युवती के मायके वालों का कहना है कि- शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। और कई बार जयंती के साथ मारपीट भी की थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष को समझा कर, दहेज के पैसे देने की बात कहकर मामले को शांत कराया था।

पति से विवाद के बाद लगाई फांसी: मंगलवार सुबह पति धर्मेंद्र, पत्नि जयंती को वापस ससुराल लाया था। देर रात पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने कथित तौर पर जयंती के साथ मारपीट की।

इसके बाद जयंती ने कमरे में जाकर रस्सी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। मृतका के ससुर ने फोन पर मायके वालों को घटना की जानकारी दी थी।

खाद के लिए रतजगा कर रहे किसान-इनमें कई आठ दिनों से इंतजार कर रहे

सीहोर, एजेंसी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किसान खाद के लिए रात भर जागने (रतजगा) को मजबूर हैं। यह स्थिति सीहोर के इछावर क्षेत्र में देखी जा रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का विधानसभा क्षेत्र है।

इछावर और बोरदी की सोसायटियों में किसान कई दिनों से या देर रात से खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

उन्हें रात भर सोसायटी परिसर के बाहर ही रुकना पड़ रहा है। कई किसानों को 8 दिनों से खाद नहीं मिल पाई है, जबकि कुछ को दो या तीन दिन बाद केवल एक या दो बोरी खाद मिल पाती है।

इछावर ब्लॉक के किसान खाद की किल्लत से बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खाद की भारी कमी है और मांग अधिक होने के कारण उन्हें रात भर जागकर नंबर लगाना पड़ रहा है, ताकि उन्हें खाद मिल सके। वे दो दिनों से इंतजार कर रहे हैं और रात भर बैठे रहने के बाद ही उन्हें खाद मिलने की उम्मीद है।

किसान भूरा सिंह परमार ने बताया, हम आठ दिन से खाद के लिए परेशान हैं। मंत्री करण सिंह वर्मा से मेरा कहना है कि यदि खाद नहीं देनी है तो हमें सेलफास दे दें। मंत्री जी मंच से हमें अन्नदाता कहते हैं, लेकिन हमें अन्नदाता नहीं, अंधे दाता कहो, क्योंकि हम आंख मूंदकर आपको वोट देते हैं। एक अन्य किसान रमेश ने बताया कि रात भर जागकर नंबर लगाने के बाद भी कुछ ही किसानों को खाद मिल पाती है और यह भी निश्चित नहीं है कि सभी को खाद मिल ही जाए।

कलेक्टर बालागुरू के. ने जिले में खाद वितरण को लेकर कहा है कि जिले में आवश्यकतानुसार खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। समय पर वितरण केन्द्रों को खुलवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद दुकानों की नियमित जांच और कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिले के लिये आवंटित खाद का पूरा उठाव और जिले में पहुंच सुनिश्चित की जाए।

पुलिस कंट्रोल रूम में हुई जनसुनवाई:एसपी की मौजूदगी में 42 आवेदकों की शिकायतों का तत्काल समाधान

मंदसौर, एजेंसी। एसपी विनोद कुमार मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आमजन की शिकायतों का त्वरित और विधिसंगत निराकरण करना है। जनसुनवाई में पुलिस अधिकारियों ने 42 आवेदकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया। एसपी ने व्यक्तिगत रूप से लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित थाना और चौकी प्रभारियों को मामलों का जल्द निराकरण करने और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आवेदकों की सुविधा के लिए जनसुनवाई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बजाय जिला पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित किया गया। कंट्रोल रूम शहर के मध्य में स्थित है, जिससे लोगों को पहुंचने में आसानी हुई और उनके समय की बचत हुई।

जनसुनवाई में एसपी विनोद कुमार मीणा के साथ एडिशनल एसपी टी.एस. बघेल, एडिशनल एसपी हेमलता कुरील, सीएसपी जितेंद्र भास्कर, एसडीओपी कीर्ति बघेल, एसडीओपी नरेंद्र सिंह सोलंकी, एसडीओपी दिनेश प्रजापति और एसडीओपी विजय यादव सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इन सभी अधिकारियों ने अपने-अपने अनुभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण में सहयोग किया। एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत, जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की जांच और निराकरण अगले सप्ताह की जनसुनवाई से पहले संबंधित अनुभाग के एसडीओपी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल से आमजन को त्वरित न्याय मिलेगा और उनके समय की बचत होगी।

सैलरी न मिलने से माचलपुर के सफाईकर्मी हड़ताल पर

दीपावली से पहले नगर कचरे से पटा, कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

राजगढ़, एजेंसी। दीपावली नजदीक है, लेकिन राजगढ़ जिले के माचलपुर नगर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नगर परिषद के 40 से अधिक सफाईकर्मी पिछले दो माह से वेतन न मिलने और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। बुधवार को हड़ताल का दूसरा दिन रहा, जिससे पूरे नगर में जगह-जगह कचरे के ढेर लग गए हैं और गलियों में बदबू फैलने लगी है।

बुधवार को कर्मचारियों ने नगर में धपली बजाते हुए रैली निकाली। इस दौरान सफाईकर्मियों ने ÷कर्मचारी एकता जिंदाबाद÷ और ÷हमारा हक दो÷ के नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले भी नगर परिषद ने उनकी सुध नहीं ली, जिससे सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं।

कचरा उठाने गए कर्मचारी से बढ़ा विवाद: नगर में गंदगी बढ़ने पर जब परिषद ने अपने कर्मचारी दीपक राठौर को कचरा वाहन देकर सफाई के लिए भेजा, तो हड़ताली सफाईकर्मी भड़क उठे। उन्होंने दीपक से कहा कि ÷सफाई करना हमारा काम है, तुम बीच में मत आओ।÷ इसके बाद दीपक को लौटना पड़ा। इससे साफ है कि हड़ताल का असर पूरे नगर में गहराई से दिखाई दे रहा है।

कर्मचारी बोले- परिवार चलाना मुश्किल: हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है

कि उन्हें पिछले दो माह से वेतन नहीं मिला है। लगातार मांग करने के बावजूद नगर परिषद द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। दीपावली जैसे त्योहार के समय घर चलाना मुश्किल हो गया है।

सफाईकर्मी संगठन ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं

- वर्ष 2018 से अब तक का ईपीएफ जमा कराया जाए।
- दो माह का बकाया वेतन तत्काल भुगतान किया जाए।
- आगे से हर माह की 15 तारीख तक नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए और सफाई के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
- अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
- कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानी गईं तो हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
- हड़ताल के कारण मंगलवार और बुधवार दोनों दिन नगर में सफाई नहीं हुई।

गिल, कोहली और रोहित ऑस्ट्रेलिया रवाना, जानिए कब होगी दूसरे जत्थे की रवानगी?

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत कुछ अन्य सदस्यों का एक ग्रुप बुधवार को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। टीम का दूसरा बैच आज रात 9 बजे रवाना होगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने वाले पहले ग्रुप में सहयोगी स्टाफ और कई वरिष्ठ खिलाड़ी भी शामिल हैं। बाकी सदस्य ऑस्ट्रेलिया में टीम के अभ्यास सत्र से पहले साथियों से जुड़ेंगे। भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19-25 अक्टूबर के बीच तीन वनडे मैच खेलेंगी, जिसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच दोनों देश पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।

दोनों देशों के बीच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहला वनडे मैच से खेला जाएगा, जिसके बाद 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच आयोजित होंगे।

भारत ने पिछली बार 2020-21 में द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जहां उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया लंबे वक्त बाद इस हार का बदला लेना चाहेगी।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि श्रेयस अय्यर के पास टीम की उपकप्तानी है। इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं।

इनके अलावा अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) टीम का हिस्सा हैं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब 6 महीनों के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। कोहली 36 साल के हैं, जबकि रोहित शर्मा 38 साल के हैं। ऐसे में उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा इन दोनों दिग्गजों के आगामी विश्व कप में खेलने की चाहत में महत्वपूर्ण चुनौती होगा।

प्यूर्टो रिको के खिलाफ अर्जेंटीना की शानदार जीत, नेमार को पछाड़कर मेसी ने रचा इतिहास

फोर्ट लॉडरडेल, एजेंसी। अर्जेंटीना ने चेज स्टेडियम में प्यूर्टो रिको के खिलाफ 6-0 से जीत दर्ज की। मुकाबले के दौरान स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दो गोल में असिस्ट किया। इसी के साथ लियोनेल मेसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन गए। अद्भुत कौशल और रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों के लिए मशहूर मेसी ने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 60 असिस्ट किए हैं। प्यूर्टो रिको के खिलाफ दो असिस्ट के साथ उन्होंने नेमार और लैंडन डोनोवन को पछाड़ दिया। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने करियर में 58-58 असिस्ट किए हैं। अब मेसी अपने पेशेवर करियर में कुल 400 असिस्ट से सिर्फ तीन ही कदम दूर हैं। प्यूर्टो रिको के विरुद्ध मुकाबले में अर्जेंटीना ने तुरंत ही गेंद पर नियंत्रण कर लिया था।

मुकाबले के 13वें मिनट मोंटील ने मेसी को क्रॉस दिया, जिन्होंने क्रॉसबार पर शॉट मारा। निकोलस गोंजालेज ने रिबाउंड पर वॉली से गेंद को गोल की ओर पहुंचाया और मैक एलिस्टर ने हेडर से गोल करके मैच का खाता खोला। मैच के 23वें मिनट मेसी ने मोंटील को एक बेहतरीन पास दिया, जिन्होंने इसे गोल में तब्दील करते हुए अर्जेंटीना के स्कोर को 2-0 पहुंचा दिया।

इसके बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी लगातार प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गोल की तलाश में लगे रहे। मैक एलिस्टर ने मुकाबले के 36वें मिनट एक और गोल किया। दूसरे हाफ में, मैदान पर कुछ बदलावों के साथ एल्बी सेलेस्टे ने मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा। 64वें मिनट तक अर्जेंटीना की टीम 4-0 से आगे थी।

79वें मिनट मेसी के एक और बेहतरीन पास के बाद, निको गोंजालेज ने गेंद को लौटारो मार्टिनेज को दिया, जिन्होंने तुरंत इसे गोल में बदलते हुए स्कोर 5-0 पहुंचा दिया। 84वें मिनट मेसी ने पीछे से एक शानदार पास दिया, जिससे मार्टिनेज ने फिर से बिना गलती किए, एक तेज और सटीक फिनिश के साथ स्कोर को 6-0 में बदल दिया।

गुवाहाटी का टेस्ट मैच बड़ी चुनौती, भारत के अगले टेस्ट मैच पर अश्विन का चौंकाने वाला बयान

चेन्नई। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि गुवाहाटी में आगामी टेस्ट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए विदेश जैसी परिस्थितियों वाला मुकाबला साबित हो सकता है। उन्होंने देश में स्थायी टेस्ट केंद्र और अच्छी पिचों की जरूरत पर भी जोर दिया।

गुवाहाटी का बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम भारत का सबसे नया टेस्ट स्थल बन जाएगा और 22 से 26 नवंबर तक विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के दूसरे और अंतिम मैच की मेजबानी करेगा, जिसमें गत विजेता दक्षिण अफ्रीका भारतीय टीम से भिड़ेगी।

अश्विन ने कहा, मैं इस मैदान पर खेलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्थायी टेस्ट केंद्र बनाने का विचार बेहद जरूरी है। मौजूदा भारतीय खिलाड़ियों में से किसी ने भी यहां लाल गेंद से टेस्ट नहीं खेला है। गुवाहाटी की परिस्थितियां भारतीय टीम के लिए भी नई होंगी।

क्या रोहित और विराट अगला विश्व कप खेलेंगे? गौतम गंभीर के जवाब से उठे सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम ने नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली। भारत का अगला दौरा ऑस्ट्रेलिया का है, जहां टीम को 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय टीम का हिस्सा हैं। नई दिल्ली टेस्ट के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों खिलाड़ियों से जुड़े सवाल पर मुख्य कोच गौतम गंभीर ने जो कहा, वो उनके भविष्य पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगाता है। गौतम गंभीर से ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 विश्व कप में खेलने की संभावना पर सवाल पूछा गया। गंभीर के जवाब ने कहीं न कहीं भारतीय टीम के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों के वनडे करियर और अगला विश्व कप खेलने की संभावना पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। गंभीर ने कहा, ÷50 ओवरों का विश्व कप अभी ढाई साल दूर है। मुझे लगता है कि वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वे वापसी कर रहे हैं, और उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में भी काम आएगा। उम्मीद है कि उन दोनों खिलाड़ियों का दौरा सफल रहेगा, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम के रूप में, हमारी सीरीज सफल रहेगी।

गंभीर के जवाब का अध्ययन करने पर दो तथ्य सामने आते हैं। एक यह कि विश्व कप ढ़ाई साल बाद है। दरअसल, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले विश्व कप तक रोहित और विराट 40 साल के करीब होंगे। ऐसे में उनकी फिटनेस बेहद अहम होगी। इसके अलावा, गंभीर ने दोनों के सफल दौरे का जिक्र किया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रोहित और विराट के बल्ले से रन आने चाहिए। उन्हें सिर्फ अनुभव और पुराने फॉर्म के आधार पर शायद ही मौका मिले। रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों का एकमात्र सपना वनडे विश्व कप 2027 खेलना और जीतना है। देखना होगा कि दोनों का यह सपना पूरा हो पाता है या नहीं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 5 बड़ी भारतीय पारियां

रोहित शर्मा शीर्ष पर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है। पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के तीन मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हमेशा संघर्षपूर्ण पूर्ण और रोमांचक होते रहे हैं। कई भारतीय बल्लेबाजों ने अपने जीवन की श्रेष्ठ पारियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली हैं। मौजूदा टीम में रोहित, विराट और गिल जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किन पांच भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में बड़ी पारियां खेली है। रोहित शर्मा का पहला एकदिवसीय दोहरा शतक नवंबर 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था। 158 गेंदों पर 12 चौकों और 16 छक्कों की मदद से बनाए गए से उन्होंने 209 रन बनाए थे। यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से वनडे की दूसरी बड़ी पारी सचिन तेंदुलकर ने खेली है। तेंदुलकर ने 2009 में 141 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हालांकि 351 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ये मैच 3 रन से हार गई थी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से तीसरी बड़ी पारी रोहित शर्मा ने ही खेली है। रोहित ने पर्थ में 2016 में 171 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से चौथी बड़ी पारी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने खेली है। 2019 में धवन ने 115 गेंद पर 143 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से पांचवीं बड़ी पारी पूर्व कप्तान धोनी ने 2013 में खेली थी। धोनी ने 121 गेंद पर 139 रन बनाए थे।

करीब 5 लाख की आबादी, काबो वर्डे ने फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया

नई दिल्ली, एजेंसी। काबो वर्डे ने पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उसने एस्वातिनी को 3-0 से शिकस्त देकर ग्लोबल फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। करीब 5 लाख आबादी वाला काबो वर्डे, विश्व कप में पहुंचने वाला आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है, जिसने साल 2018 फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया था। पहले हाफ में एस्वातिनी के खिलाफ कड़ी टक्कर के बाद, काबो वर्डे ने दूसरे हाफ में शानदार खेल दिखाया। डैलोन लिव्रामेंटो, विली सेमेडो और स्टोपिरा के गोल ने एस्तादियो नासियोनल दे काबो वर्डे में फैंस को जश्न का मौका दिया।

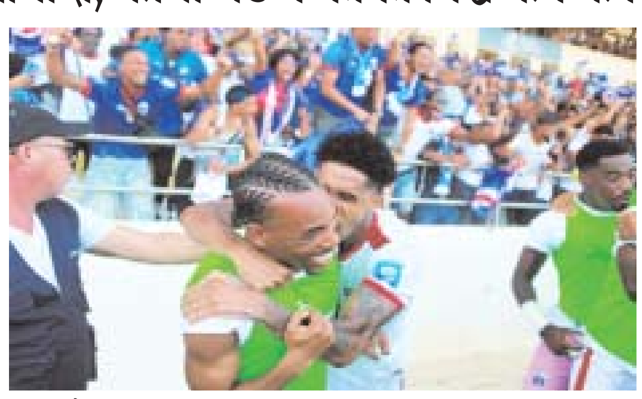

काबो वर्डे ने अंतिम समय में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालीफाई किया। पहले हाफ में तेज हवा के चलते कठिनाई झेलने के बाद, ब्लू शार्क्स ने 48वें मिनट पहली सफलता हासिल की। यानिक सेमेडो के क्रॉस पर डैलोन लिव्रामेंटो ने गोल दागा।

टीम ने लगातार आक्रमण जारी रखा। इस बीच जमिरो मोंतेइरो का दूर से शॉट क्रॉसबार से टकराया। 54वें मिनट विली सेमेडो ने रयान मेंडेस के क्रॉस पर पांच यार्ड की दूरी से गोल करके टीम को 2-0 से बढ़त दिलाई।

37 वर्षीय स्टोपिरा ने 90+1 मिनट पर गोल दागते हुए टीम को मुकाबले में 3-0 से आगे करते हुए जीत सुनिश्चित कर दी।

काबो वर्डे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाला सबसे छोटा राष्ट्र बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड त्रिनिदाद और टोबैगो के नाम था, जिसने जर्मनी में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2006 में भाग लिया। काबो वर्डे के इस ऐतिहासिक अभियान में लगातार पांच जीत शामिल थीं। इस टीम ने एस्वातिनी को हराकर फीफा विश्व कप के लिए ऐतिहासिक क्वालीफाई किया। अब 5 दिसंबर को वाशिंगटन डीसी में होने वाले ड्रॉ में काबो वर्डे को फीफा विश्व कप 26 के ग्रुप-स्टेज प्रतिद्वंद्वियों का पता चलेगा।

विश्व कप के बीच महाकाल की शरण में भारतीय महिला टीम

जीत के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया

उज्जैन, एजेंसी। विश्व कप 2025 के बीच भारतीय महिला टीम महाकाल की शरण में पहुंची है। भारतीय खिलाड़ियों ने बुधवार सुबह आस्था और आध्यात्म की नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के साथ भारतीय महिला टीम की कई खिलाड़ी यहां तड़के होने वाली भस्म आरती में शामिल हुईं। खिलाड़ी पूरी तरह भक्तिभाव में लीन होकर अपनी पूजा-अर्चना करते नजर आए। इस दौरान खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। टीम ने महाकाल के दरबार में आगामी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन और विश्व कप जीतने की कामना की।

भारत ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 19 अक्टूबर को विश्व कप 2025 का 20वां मैच खेलना है। भारतीय टीम फिलहाल 4 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है।

टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध अपने अभियान का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता था, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 88 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले दोनों मुकाबले 3-3 विकेट से गंवा दिए।

भारतीय टीम 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। भारतीय टीम इसी मैदान पर 28 अक्टूबर को बांग्लादेश को चुनौती देगी।

इस विश्व कप में प्रतिका रावल चार मुकाबलों में 45 की औसत के साथ 180 रन बनाकर भारत की शीर्ष बल्लेबाज हैं। वहीं, ऋचा घोष ने 4 पारियों में 54.33 की औसत के साथ 163 रन बनाए। हरलीन देओल 145, जबकि स्मृति मंधाना 134 रन जुटा चुकी हैं।

गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा चार मुकाबलों में 22.78 की औसत के साथ 9 विकेट लेकर शीर्ष भारतीय गेंदबाज हैं। वहीं, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा 6-6 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं।

संजू सैमसन की केरल रणजी टीम में वापसी

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। संजू सैमसन का नाम केरल की रणजी ट्रॉफी टीम में वापस आ गया है और इसके साथ ही उत्सुकता, उत्साह और शांत जिज्ञासा की लहर आ गई है। केरल 15 अक्टूबर से तिरुवनंतपुरम में अपने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में महाराष्ट्र का सामना करने के लिए तैयार है, ऐसे में विकेटकीपर-बल्लेबाज की लाल गेंद क्रिकेट में वापसी एक तरह से घर वापसी और सामंजस्य दोनों का प्रतीक है।

संजू सैमसन को आखिरी बार प्रथम श्रेणी मैच खेले हुए लगभग एक साल हो गया है, उनका पिछला मैच कर्नाटक के खिलाफ था। पिछले एक साल में, उनका ध्यान मुख्य रूप से सफेद गेंद के प्रारूपों पर केंद्रित रहा है, जिसमें उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का नेतृत्व किया और भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में भी शामिल रहे। अब, जब वह एक बार फिर केरल की सफेद जर्सी पहन रहे हैं, तो सैमसन के पास लाल गेंद क्रिकेट की मांग वाले कौशल और धैर्य को फिर से दिखाने का मौका है। केरल के चयनकर्ताओं ने कप्तानी मोहम्मद अजहरुद्दीन को सौंप दी है, जबकि बाबा अपराजित को उप-कप्तान बनाया गया है। यह कदम टीम के निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है, जबकि सैमसन इस महीने के अंत में राष्ट्रीय टीम के लिए तैयारी कर रहे हैं।

पाकिस्तान की हार पर कोच अजहर महमूद का सख्त बयान, खुद की गलती से गंवाया मैच

नई दिल्ली, एजेंसी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की हार ने कोच अज़हर महमूद को झकझोर कर रख दिया। एक समय मेजबान टीम मजबूत स्थिति में थी, 6 विकेट बाकी रहते 259 रनों की बढ़त। लेकिन 45 मिनट के भीतर ही पूरा बल्लेबाज़ी क्रम ध्वस्त हो गया और पाकिस्तान महज 17 रन जोड़कर ऑलआउट हो गया। दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने हासिल कर मेजबानों से मैच छीन लिया।

हार की वजह हमारा शॉट चयन- अजहर महमूद का बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़हर महमूद ने टीम के प्रदर्शन पर नाराज़गी जताते हुए साफ कहा कि हार का कारण सिर्फ पिच नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की खराब सोच और जल्दबाजी है। उन्होंने कहा, हम खुद को मुश्किल में डाल बैठे। जब हमारा स्कोर 150/4 था, तब मैच पूरी तरह हमारे नियंत्रण में था। लेकिन हमने 6 विकेट 17 रन पर गंवाए — इसके लिए पिच नहीं, बल्कि हमारे शॉट चयन और निर्णय जिम्मेदार हैं। कोच ने दो टूक कहा कि बल्लेबाज़ों को धैर्य और तकनीक से काम लेना होगा, खासकर धीमी पिचों पर।

पाकिस्तान की कमजोरियाँ पहली पारी में ही दिख गई थीं, जब टीम ने 199/2 से बिना रन जोड़े तीन विकेट गंवा दिए। मोहम्मद रिज़वान और सलमान आगा की 163 रनों की साझेदारी ने टीम को संभाला जरूर, लेकिन बाद में फिर ढह गई।

अज़हर ने कहा, हमने कई बार देखा है कि शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन बल्लेबाज़ उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते। यही वजह है कि हमारे पास बढ़त लेने का मौका होते हुए भी हम मैच गंवा देते हैं।

पिच पर बल्लेबाजी आसान थी, बस धैर्य की कमी रही

कोच ने पिच की आलोचना करने से इनकार करते हुए कहा कि यह बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किल नहीं थी, बल्कि मानसिक संतुलन का मामला था। उन्होंने कहा, यह कोई असमान पिच नहीं थी। अगर आप टिककर खेलते, तो रन बनाना आसान था। लेकिन जैसे ही बल्लेबाज दबाव में आए, उन्होंने गलत शॉट चुने। यह मानसिक दृढ़ता का खेल है – न कि सिर्फ तकनीक का।

झिरिया जलाशय योजना को मिली पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

सिमगा क्षेत्र के 250 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड सिमगा स्थित झिरिया जलाशय योजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की कुल स्वीकृत लागत 9 करोड़ 78 लाख 19 हजार रुपए निर्धारित की गई है। यह स्वीकृति राज्य शासन द्वारा महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर से जारी की गई है। योजना के पूर्ण होने पर विकासखंड सिमगा के लगभग 250 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषक वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। यह परियोजना क्षेत्र के जल संसाधनों के समुचित उपयोग और ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। स्वीकृत योजना के अंतर्गत कार्य निर्धारित समय सीमा और स्वीकृत लागत राशि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा ड्रॉइंग एवं डिजाइन का अनुमोदन सुनिश्चित किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से की जाएगी। कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग, रायपुर को निर्देशित किया गया है कि कार्यों में प्रशासकीय और वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए तथा स्वीकृत राशि एवं समयावधि के भीतर कार्य पूर्ण किया जाए। झिरिया जलाशय योजना के माध्यम से सिमगा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि और जल उपयोग दक्षता में सुधार होगा। यह योजना राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत बनाएगी।

जशपुर जिले में खारूंग नदी पर भेलवा एनीकट योजना को मिली प्रशासकीय स्वीकृति

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा जशपुर जिले के विकासखंड फरसाबहार की खारूंग नदी पर भेलवा एनीकट योजना कार्य हेतु 5 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति राज्य शासन द्वारा जारी की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामवासियों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन तथा कृषकों द्वारा स्वयं के साधनों से लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ाने, भू-जल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करने और स्थानीय कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से तैयार की गई है।

निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाएगी। योजना की ड्रॉइंग एवं डिज़ाइन का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा तभी की जाएगी जब कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध हो। कार्य की निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संपन्न की जाएगी। भू-अर्जन की आवश्यकता होने पर व्यय स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर किया जाएगा तथा किसी अन्य मद से राशि का स्थानांतरण बिना पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जाएगा। यदि भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं है, तो निर्माण कार्य केवल शासकीय भूमि पर ही कराया जाएगा। निर्माण कार्य के दौरान प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

कार्य को स्वीकृत लागत एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय-सीमा में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार समय में बढ़ोतरी प्रदान किया जा सकेगा। निर्माण कार्य की निविदा दर या प्रस्तावित मात्रा में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कार्य के सभी तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं का पालन छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार किया जाए तथा योजना की लोकहित, गुणवत्ता और मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। भलवा एनीकट योजना के माध्यम से फरसाबहार क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल, सिंचाई और जल संरक्षण की दीर्घकालिक सुविधा प्राप्त होगी। यह योजना राज्य शासन की ग्रामीण विकास, जल संवर्धन एवं कृषि सशक्तिकरण के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

छत्तीसगढ़ में 'तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल-कॉलेज अभियान' प्रारंभ

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। भारत सरकार द्वारा 'तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 (Tobacco Free Youth Campaign – TFYC x.®) का शुभारंभ 9 अक्टूबर 2025 को किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू एवं नशे की लत से दूर रखना, उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना तथा जो तंबाकू सेवन छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सहयोग प्रदान करना है। अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 'तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (ञ्चह्रस्नश्वढ्ढ) बनाने दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया है।

'तंबाकू और नशा मुक्त अभियान चलाने निर्देश': छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में 'तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल-कॉलेज अभियान' चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में भारत सरकार के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त संयुक्त पत्र के संदर्भ में सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजा गया है।

'तम्बाकू के दुष्परिणाम से युवाओं को जागरूक कराना': भारत में युवाओं में तंबाकू सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बनी हुई है। पारंपरिक तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पानमसाला के साथ-साथ ई-सिगरेट और निकोटीन पाउच जैसे नए स्वरूप युवाओं में तेजी से फैल रहे हैं। तंबाकू शरीर के लगभग सभी अंगों को प्रभावित करता है और सिर, गर्दन, ग्रासनली, फेफड़े एवं मुख कैंसर के अधिकांश मामलों का प्रमुख कारण है। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.4 प्रतिशत स्कूली बच्चे तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है।

'शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि पर तंबाकू बिक्री पूर्णतः प्रतिबंध' अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले को यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के मानकों को अपनाएं। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान, छात्र परामर्श सत्र, एनएसएस/एनसीसी स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा तंबाकू के दुष्प्रभावों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही, शैक्षणिक परिसरों के चारों ओर 100 गज की परिधि निर्धारित कर तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा।

बस्तर ओलंपिक के व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए विकासखंड स्तरीय आयोजनों पर दें विशेष ध्यान

अब तक 2.72 लाख खिलाड़ियों का पंजीयन, 20 अटूबर तक करा सकते हैं पंजीयन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। बस्तर ओलंपिक-2025 की तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों तथा बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में बस्तर ओलंपिक के व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए विकासखंड स्तरीय आयोजनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल मैदानों की उपलब्धता, उनकी मैपिंग, भोजन, यातायात, आवास, प्राथमिक चिकित्सा, निर्णायकों एवं रेफरियों की व्यवस्था के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और संचालक तनूजा सलाम भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थीं। बस्तर संभाग के सभी जिला खेल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में बस्तर ओलंपिक की पंजीयन प्रक्रिया एवं व्यापक प्रचार-प्रसार की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रचार-प्रसार की योजनाओंकृजैसे दीवार लेखन, मशाल यात्रा, पोस्टर, बैनर, पैंपलेट वितरण, हाट-बाज़ारों में प्रचार इत्यादि की जानकारी ली। उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस्तर ओलंपिक के लिए अब तक 2 लाख 72 हजार से अधिक प्रतिभागियों का पंजीयन हो चुका है। 20 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जा सकता है। इस पर श्री साव ने प्रत्येक विकासखण्ड में पंजीयन की स्थिति की समीक्षा कर जिन क्षेत्रों में पंजीयन कम हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं की तुलना में पुरुष प्रतिभागियों के कम पंजीयन को देखते हुए जिला खेल अधिकारियों को पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा।

श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर ओलंपिक अब केवल क्षेत्रीय आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि इसकी ख्याति पूरे देश में फैल चुकी है। अतः इसे राष्ट्रीय महत्व का आयोजन मानते हुए विकासखंड से लेकर संभाग स्तर तक उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ आयोजित किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के निर्णायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रेरणा स्रोत के रूप में आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक होने वाले विकासखंड स्तरीय आयोजनों के लिए सभी जिलों को समय पूर्व संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे खेलों में पंजीयन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने तथा खेल विभाग से प्राप्त बजट के अतिरिक्त जिला कलेक्टरों के सहयोग से सीएसआर निधि से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने को कहा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक रश्मि ठाकुर तथा खेल अधिकारी गिरीश शुक्ला भी बैठक में मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से महिलाओं के जीवन में आ रहा है बदलाव

नवागांव की संतोषी ने कहा- सरकार बनी परिवार की नई उम्मीद

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास, उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन, हर महीने निःशुल्क अनाज और महतारी वंदन की राशि मिलने से पेंड्रा विकासखंड के नवागांव की संतोषी श्रीवास सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। संतोषी ने बताया कि पक्का मकान मिलने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है।

सुरक्षित एवं सुविधाजनक पक्का घर मिला: संतोषी श्रीवास ने बताया कि पहले उनका घर कच्चा था, जिससे बरसात के दिनों में बहुत परेशानी होती थी। घर की दीवारों में सीलन आ जाती थी, जिससे रहना मुश्किल हो जाता था। बच्चों की भी पढ़ाई में दिक्कत होती थी, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई के लिए उचित जगह नहीं थी। परिवार की आमदनी कम होने के कारण वे पक्का घर बनवाने में असमर्थ थीं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से उनका घर अब सुरक्षित, सुविधाजनक पक्के घर में बदल गया। अब उनका परिवार आराम से सुरक्षित घर में रह रहा है।

शासन की योजनाओं का लाभ लेकर खुशहाल हुई संतोषी: उज्ज्वला योजना ने उनकी रसोई से धुआं और लकड़ी की मशक्कत खत्म की और मुफ्त गैस कनेक्शन ने स्वास्थ्य के साथ समय और ईंधन दोनों की बचत हुई। राशन कार्ड के अंतर्गत हर माह 35 किलो चावल और महतारी वंदन योजना की 1000 रुपये की राशि से छोटे-छोटे खर्च भी आसानी से पूरे हो जाते हैं।

सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे घर-पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढते कदम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सौर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त एवं स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का संचालन किया जा रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में नागरिकों के घर सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं। आमजन अपने घरों में मुफ्त बिजली का लाभ लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर सकरात्मक कदम बढ़ा रहे हैं। शासन द्वारा सब्सिडी मिलने से योजना का लाभ लेना अधिक आसान हो गया है।

12 हजार घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य: मुंगेली जिले में यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके तहत हर घर सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनेगा। मुंगेली जिले में 2025-26 के लिए जिले में 12 हजार घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है।

सौर संयंत्र के लिए जिले में 633 आवेदन प्राप्त: विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जिले में अब तक 633 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 238 आवेदकों ने वेंडर का चयन कर लिया है। इनमें से 50 आवासों में सौर संयंत्र का कार्य पूरा हो चुका है। विभागीय निरीक्षण हेतु 40 मामलों को स्वीकृति मिली है, अब तक 18 उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन को योजना की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

3 किलोवाट तक एक लाख 08 हजार रूपए तक अनुदानः योजना के तहत उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकता अनुसार 01 किलोवाट से 03 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवा सकते हैं।

स्वस्थ रहने के लिए दैनिक आहार में श्री अन्न शामिल करें

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं कृषक कल्याण परिषद (छ.ग.) के सयुक्त तत्वाधान में श्री अन्न (मिलेट) की उपयोगिता विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन सेमिनार हाल, कृषि महाविद्यालय रायपुर में आज किया गया। इस कार्यक्रम में पदम् डॉ. खादर वली, (मिलेट मैन ऑफ़ इंडिया) ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर संकाय सदस्यों, शोधार्थियों तथा विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेन्द्र चंद्रवंशी, अध्यक्ष, कृषक कल्याण परिषद एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ आरती गुहे, अधिष्ठाता, डॉ विवेक कुमार त्रिपाठी, संचालक अनुसंधान सेवाये एवं डॉ एस एस टुटेजा, निर्देशक विस्तार सेवाएं उपस्थित थे। मुख्य वक्ता पदम् डॉ. खादर वली ने अपने संबोधन में बताया कि भारत में एक समय श्री अन्न (मिलेट्स) का व्यापक रूप से उत्पादन और उपभोग किया जाता था। ये फसलें न केवल जलवायु के अनुरूप होती हैं, बल्कि बहुत कम पानी एवं उर्वरकों में भी अच्छी पैदावार देती हैं। मिलेट्स को उगाने के लिए 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। ये सी4 श्रेणी के पौधे हैं जो कम संसाधनों में अधिक उत्पादकता देते हैं और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार मिलेट्स का पुनः प्रसार भारत के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

उन्होंने बताया कि हरित क्रांति के पश्चात गेहूं और धान की ओर झुकाव बढ़ा, जिससे पारंपरिक फसलों की अनदेखी हुई तथा किसानों के अधिकार भी प्रभावित हुए, परंतु मिलेट्स को अपनाकर हम एक बार फिर सतत कृषि प्रणाली को सशक्त बना सकते हैं।

श्री अन्न के स्वास्थ्य पर प्रभाव के संदर्भ में डॉ खादर वली ने बताया कि मिलेट्स में प्राकृतिक रेशे (फाइबर) की मात्रा अधिक होती है, जो पाचनतंत्र के लिए लाभकारी है और शुगर, हृदय रोग जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में मददगार है। उन्होंने बताया कि पारंपरिक आहार न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।

कार्यक्रम के अंत में उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों एवं विद्यार्थियों से मिलेट्स पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि अगले कुछ वर्षों में लोग मिलेट्स को अपने दैनिक आहार में पुनः शामिल करें, तो भारत स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों क्षेत्रों में एक उदाहरण बन सकता है।

कार्यक्रम के समापन में प्रतिभागियों को मिलेट न्यूट्री के विभिन उत्पाद ज्वार चिवड़ा, पीनट कूकीज, कोदो ग्लूटेन फी कूकीज, बाजरा पोप्स एवं रागी पापड़ी का वितरण किया गया इस कार्यक्रम में 200 से अधिक संकाय सदस्य शोधार्थी तथा विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. शुभा बेनर्जी, सहायक प्राध्यापक ने किया।

जिले को मिला मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कोटा, श्रद्धालुओं को मिलेगा मथुरा-वृंदावन दर्शन का सौभाग्य

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक भावना को सम्मान देते हुए निरंतर रूप से संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए भी एक नया अवसर प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत जिले के 10 पात्र तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है जिन्हें आगामी 20 नवम्बर से 23 नवम्बर 2025 तक पवित्र स्थल मथुरा, वृंदावन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि की धार्मिक यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होगा। शासन द्वारा की जा रही यह पहल न केवल वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आकांक्षा को पूरा करने की दिशा में एक कदम है बल्कि यह समाज के उन वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक भी है, जो आर्थिक अभाव या सामाजिक परिस्थिति के कारण तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ रहते हैं। इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को दिया जाएगा जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तथा शारीरिक और मानसिक रूप से तीर्थ यात्रा के योग्य हैं। इच्छुक पात्र जन अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 05 नवम्बर 2025 तक अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं समानता सुनिश्चित करने हेतु शासन ने स्पष्ट प्रावधान किए हैं। योजना में 80 प्रतिशत लाभार्थी बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्य योजना कार्ड धारक होंगे, जबकि 20 प्रतिशत लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर के वे नागरिक होंगे जो आयकरदाता नहीं हैं।

अंग्रेजी हुकूमत काल के जनजातीय विद्रोहों पर आधारित संग्रहालय को दिया जा रहा अंतिम स्वरूप

ओरिएंटेशन रूम की डायूड्रामा हल्बी-गोंडी सहित अंन्य जनजातीय बोलियों में तैयार करने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। अंग्रेजी हुकूमत के काल में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शौर्य और बलिदान की स्मृति में नवा रायपुर, अटल नगर में निर्मित किए जा रहे भव्य संग्रहालय-सह-स्मारक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर इस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव विकास शील ने आज निर्माण स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर बनाया जा रहा यह संग्रहालय देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों के साथ-साथ जंगल सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह पर अलग-अलग गैलरियाँ बनाई जा रही हैं। संग्रहालय में आगंतुकों को इन जनजातीय आंदोलनों की जीवंत झलकें देखने और सुनने को मिलेंगी।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव शील ने कहा कि संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सामग्री को उनके मूल स्वरूप में ही प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ओरिएंटेशन रूम में प्रदर्शित की जाने वाली डाक्यूड्रामा हल्बी-गोंडी या अन्य जनजातीय बोलियों में तैयार की जाए, ताकि यह स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव का सशक्त माध्यम बन सके। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी गैलरियों का भ्रमण किया और आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने वाले आदिवासी विद्रोहों का संक्षिप्त परिचय देते हुए पूरे रूट चार्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आज ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा की। बोरा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर है कि देश का पहला पूर्णतः डिजिटल आदिवासी संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से लोकार्पित होने जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आग्रह किया। प्रमुख सचिव बोरा ने प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण रूट-प्लान के अनुसार अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, संग्रहालय तक आने वाले पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संग्रहालय क्षेत्र में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा गार्डनिंग और वृक्षारोपण की आवश्यक तैयारियाँ भी समय पर पूरी हों।

उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय होगा। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख आदिवासी विद्रोहों–हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, रानी चौरिस विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, सोनाखान विद्रोह, तथा झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह–के वीर नायकों के संघर्ष और शौर्य को 14 गैलरियों में जीवंत रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा